● वर्ष : 17 ● अंक : 232 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

दैनिक लोकतंत्र की शान

WWW.LKSTV.IN

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित शुक्रवार 12 जून 2026

केंद्र और राज्य मिलकर दे सकते हैं 'विकसित भारत' के साझा लक्ष्य को गति : प्रधानमंत्री

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र और राज्य विकास के साझेदार के रूप में मिलकर कार्य करें तो भारत 'विकसित भारत' के साझा लक्ष्य की दिशा में और अधिक तेजी से आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। नीति आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि दुनिया इस समय अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सभी की सामूहिक जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और अनुभवों का आदान-प्रदान विकास का आधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक प्रभावी मंच बन सकता है। राज्य एक-दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मिलकर कार्य कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिनसे विकास और निर्यात के नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौते सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए भी वैश्विक बाजारों में प्रवेश का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। इसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति एक ऐतिहासिक अवसर है। इसे खोया नहीं जा सकता। युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मांग आधारित कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। सशक्त युवा विकसित भारत की यात्रा के प्रमुख प्रेरक बनेंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व वाला विकास विकसित भारत की परिकल्पना का महत्वपूर्ण आधार है। कृषि, स्टार्टअप, विज्ञान और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। राज्यों को महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि उनकी पूरी क्षमता का उपयोग देश के विकास में हो सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी नेताओं की शुभकामनाओं पर जताया आभार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के लिए मिली शुभकामनाओं को लेकर गुरुवार को न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड सहित विश्व के अनेक नेताओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कई पोस्ट के जरिए इन नेताओं को धन्यवाद दिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की शुभकामनाओं के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वह इस सकारात्मक गति को आगे बढ़ाते हुए द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्सुक हैं। इससे पहले लक्सन ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को भारत का सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा था कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने में उनके साथ काम करना सुखद रहा और आने वाले वर्षों में दोनों देशों के सहयोग की व्यापक संभावनाओं को लेकर वह आशान्वित हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा के संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जापान-इंडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि किशिदा के नेतृत्व में यह संगठन भारत और जापान के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। किशिदा ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को 4,000 दिनों से अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए बधाई देते हुए उनके भावी प्रयासों की सफलता की कामना की थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह उनकी मित्रता और भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने के प्रति उनके निरंतर समर्थन को अत्यंत महत्व देते हैं।

ज्वलंत मुद्दा **संपादकीय**

मानसून सत्र और भारतीय राजनीति का समुद्र मंथन

यह चर्चा तेज है कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट देखने को मिल सकती है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। पिछले सत्र में परिसीमन बिल सरकार संसद में पास नहीं करा पाई थी। बीते महीनों में जिस तरह से सरकार को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, विदेशी निवेशक शेयर बाजार से निवेश किया धन वापस निकाल रहे हैं।

कच्चे तेल के आयात से सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार मानसून सत्र में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। देश में खाद्य पदार्थों, ईंधन और घरेलू जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों को लेकर जनता के बड़े वर्ग में नाराजगी दिखाई दे रही है। किसान संगठन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), फसल खरीद और कृषि लागत जैसे मुद्दों पर आंदोलित हैं। वहीं नीट पेपर लीक से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र संगठनों की ओर से सड़क पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। काकरोच के नाम पर युवा जेन-जी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी दलों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सरकार के दबाब में काम करने के आरोप हैं। जबकि सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है।

सरकार अपने कार्यकाल में हुए विकासकार्यों, कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक उपलब्धियों को सामने रखती है। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती बयानबाजी ने संसद के आगामी सत्र को और महत्वपूर्ण बना दिया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही संसद सत्र के पहले अपने-अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस बार विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद का मानसून सत्र आने वाले विधानसभा चुनावों और भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में यह मानसून सत्र सरकार के लिए संकटभरा हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को यदि समुद्र मंथन की उपमा दी जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। समुद्र मंथन में जिस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के साथ-साथ सहयोग भी था, उसी प्रकार भारतीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस पौराणिक कथा में पहले विष निकला और अंत में अमृत प्राप्त हुआ था। लोकतंत्र के इस राजनीतिक मंथन से मानसून सत्र में कौन लाभान्वित होगा और किसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है।

सैयद जकी हैदर | सम्पादक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

सुप्रीम कोर्ट: गृहणियां अब राष्ट्र निर्माता, मासिक मूल्य 30,000 तय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गृहणियों के संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें उन्हें केवल होममेकर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता (नेशन बिल्डर) बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि घर और परिवार की देखभाल में उनके योगदान का महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य है, जिसे अनदेखा नहीं कर सकते है। इस योगदान को मान्यता देकर सर्वोच्च न्यायालय ने गृहणियों की मासिक आय 30,000 निर्धारित की है। जस्टिस संजय करोल और कोटिस्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा, घरेलू महिलाएं घर में योगदान देती हैं। वे राष्ट्र निर्माता हैं। वे राष्ट्र का निर्माण करती हैं। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने होममेकर शब्द को अब नेशन बिल्डर की पहचान भी मिलने की उम्मीद जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुआवजे की गणना करते समय घरेलू देखभाल सेवाओं के नुकसान को एक अलग मद के रूप में शामिल किया जाए, और इसके लिए गृहणी की काल्पनिक मासिक आय 30,000 रुपये तय की गई। यह फैसला गृहणियों के अमूल्य श्रम को कानूनी और आर्थिक मान्यता प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कि देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश इस विषय की निगरानी करने , ताकि गृहणियों के योगदान को उचित और न्यायसंगत कानूनी मान्यता मिल सके। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गृहिणियों का घरेलू श्रम और परिवार की देखभाल में दिया गया समय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस अब मुआवजे के निर्धारण में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाएगी।

इजराइली सेना ने अल-अक्सा मस्जिद परिसर में चार इमारतों के ताले तोड़े

यरुशलम। यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद जो इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, एक बार फिर विवादों में आ गई है। फिलिस्तीनी निगरानी संगठन अल-कुद्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने मस्जिद परिसर में मौजूद चार अहम इमारतों को खाली करा दिया है। ये सभी इमारतें जॉर्डन समर्थित इस्लामिक वक्फ के प्रशासनिक और धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संगठन का कहना है कि इजराइली अधिकारियों ने सुरक्षा खतरे का हवाला देकर इन इमारतों को निशाना बनाया। आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में इजराइली सेना ने इन परिसरों पर छापे मारे, उनके ताले तोड़ दिए और नए ताले लगाने की इजाजत भी नहीं दी। इसके बाद इन इमारतों को खुला छोड़ दिया गया और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने से रोका गया। खाली कराए गए चार परिसरों में इमाम अल-गजाली गुम्बद, दार अल-हदीस अल-शरीफ, कुब्बत सुलेमान और कुब्बत मूसा शामिल हैं। खास बात यह है कि ये चारों इमारतें अल-अक्सा परिसर के चार अलग-अलग कोनों में स्थित हैं। इसी वजह से फिलिस्तीनी संगठन इसे कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित कदम मान रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल-कुद्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का दावा है कि इन परिसरों को खाली कराने का मकसद भविष्य में इजराइली पुलिस और प्रशासन के लिए वहां स्थायी नियंत्रण स्थापित करने का रास्ता तैयार करना है।

विदिशा में 14 जून को रखी जाएगी कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला

एजेंसी। नई दिल्ली

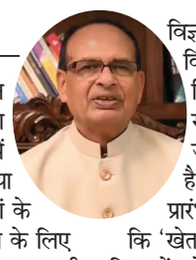

मध्यप्रदेश के विदिशा में 14 जून को कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। यह केंद्र कृषि क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा । इस केंद्र के बनने से यहां के किसानों को वैज्ञानिक रूप से खेती के लिए सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा लाभ मिल सकेगा। गुरुवार को वीडियो सन्देश जारी कर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 14 जून विदिशा संसदीय क्षेत्र की खेती और किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। 14 जून को सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, यह कृषि विज्ञान केंद्र भारत का एक मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिले का हमने जो वैज्ञानिक कृषि रोडमैप बनाया है, उसको क्रियान्वित करने का काम प्रारंभ किया जाएगा। चौहान ने कहा कि 'खेत बचाओ अभियान' के अंतर्गत भी किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। नकली खाद को कैसे पहचानें, उससे कैसे बचें, आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से फसलों की बुआई, आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन, मशीनों का प्रदर्शन, स्टॉल और सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। उन्होंने आग्रह किया कि किसान खेती को समयानुकूल बनाने के लिए इस कार्यक्रम में आकर परामर्श लें।

कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन, महंगाई, पेपर लीक के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन का किया ऐलान

एजेंसी। नई दिल्ली

कांग्रेस प्रश्नपत्र लीक, पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज किए जाने और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर अगले दो से तीन महीने में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। आंदोलन ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित किया जाएगा। इसकी विस्तृत रूपरेखा अगले कुछ दिनों में पार्टी जारी करेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को यहां पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की करीब तीन घंटे चली बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। वेणुगोपाल ने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला था, न एफआईआर और न ही कोई आरोपपत्र। इसके बावजूद उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी ओर झारखंड में भाजपा समर्थित एक कॉरपोरेट उम्मीदवार के नामांकन पत्र में कई विसंगतियां होने के बावजूद उसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी की जा रही है। कांग्रेस इस मामले को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लड़ेगी। वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक में देश की वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

अमेरिकी हमले में भारतीयों की मौत पर भारत ने जताया कड़ा विरोध

नई दिल्ली। केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को बताया कि ओमान की खाड़ी में एक टैंकर पर अमेरिकी हमले में लापता तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। ओमान के पास टैंकर पर अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हमले के बाद ये नाविक लापता बताए जा रहे थे। अमेरिका के मुताबिक निर्देशों का पालन न करने पर उसकी सेना ने जहाज पर सटीक हमला किया। अमेरिका ने यह भी कहा कि टैंकर ईरान से तेल ले जा रहा था। इस बीच जानलेवा हमले के बाद नई दिल्ली ने अमेरिकी डिप्टी चीफ़ ऑफ़ मिशन को तलब किया और हमले का कड़ा विरोध किया। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने टैंकर सेटेबेल्लो पर हमले के बाद अमेरिका के चार्ज डीअफेयर्स जेसन मीक्स को तलब किया। इस घटना के बाद भारत ने हमले की कड़ी निंदा की और जहाज पर मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हम आज ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज सेटेबेल्लो पर हुए हमले की निंदा करते हैं।

राष्ट्रपति शुक्रवार से उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 12 जून से उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह 13 जून को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी और पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार को जारी जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मु 13 जून को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति भावी सैन्य अधिकारियों की परेड का निरीक्षण करेंगी तथा प्रशिक्षण पूरा करने वाले कैडेटों की उपलब्धियों का अवलोकन करेंगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड भारतीय सेना के लिए नए अधिकारियों के औपचारिक रूप से सेना में शामिल होने का महत्वपूर्ण अवसर होती है।

विधानसभा चुनावों और टीएमसी में चल रही फूट को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक

बैठक में राहुल गांधी, वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और कई नेता रहे मौजूद

एजेंसी। नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में गुरुवार को एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों की अहम बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और कई अन्य नेता मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं की यह अहम बैठक हालिया विधानसभा चुनावों और टीएमसी में चल रही फूट के बीच हुई। इस बैठक से एक दिन पहले वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए यह आपात बैठक बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को हुई बैठक में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों के अलावा बीजेपी द्वारा केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के प्रचार अभियान और पीएम नरेंद्र मोदी के जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ने से जुड़े राजनीतिक विमर्श का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की। पार्टी नेतृत्व दल-बदल की बढ़ती घटनाओं और विपक्षी दलों के बीच समन्वय को मजबूत करने के मुद्दे पर भी विचार किया गया। राज्यों में संभावित सहयोगी दलों के साथ तालमेल बढ़ाने और विपक्षी गठबंधन के विस्तार को लेकर मंथन हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस बैठक में टीएमसी के कुछ सांसदों के लोकसभा में अलग समूह के रूप में बैठने और बीजेपी नीत सरकार की प्राथमिकताओं के साथ जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस विपक्षी एकजुटता बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की गई।

ईरान, बहरीन, कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार, होर्मुज बंद, अमेरिका की चेतावनी-अब सिर्फ बमों से होगी बात

तेहरान/वाशिंगटन/ कुवैत सिटी/ मनामा

अमेरिका ने ईरान को दिन में तारे दिखा दिए हैं। अमेरिका की सेना इस समय भी ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से से हमले कर रही है। ईरान ने भी होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करते हुए अमेरिका के साथी देशों बहरीन और कुवैत पर हमले शुरू कर दिए हैं। इससे समूचे मध्य पूर्व में सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया है। गल्फ न्यूज, अल जजीरा और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। तेहरान का कहना है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने गुरुवार सुबह कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी मध्य कमान का कहना है कि आत्मरक्षा के लिए हमले जारी रहेंगे। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिका ने रात भर पूरे ईरान पर ताजा हमले किए। इससे तीन महीने से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिशें रुक गईं। तेहरान ने चेतावनी दी कि अब कोई जहाज होर्मुज से गुजर कर दिखाए। तेहरान ने कहा कि बहरीन और कुवैत में जहाजों और अमेरिकी संपत्तियों पर हमला किया गया है। वाशिंगटन ने कहा कि इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद करने का दावा झूठा है। कमर्शियल टैंकर गुजर रहे हैं। कुवैत की सेना ने कहा कि देश पर लगातार हमले हो रहे हैं। वायु रक्षा प्रणाली ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। आईआरजीसी ने कहा कि बहरीन पर भी हमला किया गया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार, अली और अहमद एयर फोर्स बेस पर अमेरिकी सेना के 18 महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। शेख ईसा एयर बेस को उड़ा दिया गया है। बहरीन के गृह मंत्रालय गुरुवार सुबह कहा कि देश पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। उल्लेखनीय है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा तैनात है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने कल भी ईरान पर हमला किया था, आज उससे भी बड़ा हमला होगा। अमेरिका किसी को भी नहीं डरता। जिस दिन चाहेगा, नेतृत्व का झंडा उठाने वालों का हश्र सर्वोच्च नेता खामेनेई जैसा करेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला किया है। इसके अलावा केशम द्वीप और दक्षिण के शहर सिरिक और मिनाब में जोरदार धमाके हुए हैं।

13 जून तक दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में ओले व बारिश की संभावना

नई दिल्ली। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे लोगों राहत मिल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। 13 जून तक दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली कड़कने, ओलावृष्टि और व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम की सबसे ज्यादा हलचल 11 और 12 जून को देखने को मिलेगी, जिससे बढ़ते पारे से बड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में जिसमें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र और उत्तर भारत के आस-पास के इलाके शामिल हैं बिजली कड़कने, तेज़ हवाओं और ओले गिरने के साथ आंधी-तूफान आ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में अगले पांच से सात दिनों में कुछ जगहों पर 7 सेमी से 20 सेमी तक बारिश हो सकती है। दक्षिण के राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी भारी बारिश का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में 12 सेमी से 20 सेमी के बीच बारिश दर्ज की गई।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

संक्षिप्त समाचार

सीबीआई ने जॉर्जिया से वांछित का प्रत्यर्पण कराया

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जॉर्जिया से वांछित वैन्केट गर्ग का प्रत्यर्पण कराया है। गर्ग हरियाणा पुलिस के कई मामलों में वांछित है, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, संगठित अपराध और अवैध हथियारों का इस्तेमाल शामिल है। उसे जॉर्जिया में गिरफ्तार करने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी पर गुरुवार को भारत लाया गया। सीबीआई ने बताया कि सक्रिय समन्वय के तहत हरियाणा पुलिस की एस्कॉर्ट टीम जॉर्जिया गई। यह टीम वैन्केट गर्ग को लेकर 11 जून को दिल्ली पहुंची, जहां उसे सीबीआई ने हिरासत में लिया। इस कार्रवाई में सीबीआई को विदेश मंत्रालय गृह मंत्रालय और हरियाणा पुलिस ने सहयोग किया। इंटरपोल चैनलों के माध्यम से एनसीबी-नई दिल्ली ने वैन्केट गर्ग के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया था। इसके आधार पर जॉर्जियाई अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया और भारत के अनुरोध पर प्रत्यर्पण की अनुमति दी। एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की दुर्घटना पर मानवाधिकार आयोग का आन्ध्र सरकार को नोटिस

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हुई दुर्घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। 8 जून (सोमवार) को हुई इस दुर्घटना में आठ मजदूरों की मौत हो गई थी और छह अन्य के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर दो सप्ताह के अंदर इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अनुसार इस घटना को लेकर मजदूर संघ ने प्रबंधन पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। आयोग ने मांगी गई रिपोर्ट में घायल मजदूरों की सेहत की स्थिति, उन्हें और मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि का दिए जाने विवरण भी शामिल करने का निर्देश दिया है।

एपीएसबीसीएल परिवहन घोटाले में ईडी के छापे, नकदी और लग्जरी सामान बरामद

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) परिवहन घोटाले में पांच ठिकानों पर गुरुवार को तलाशी अभियान चलाया। इस मामले में सरकारी खजाने को लगभग 195.33 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने और अपने व सहयोगियों के लिए अवैध लाभ कमाने का आरोप है।ईडी ने तलाशी के दौरान आठ लाख रुपये नकद, दो रोलेक्स घड़ियां, प्रीमियम वाहन, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। एजेंसी ने बताया कि तलाशी अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चलाया गया। ईडी ने कहा कि आरोपितों ने परिवहन अनुबंधों में हेरफेर कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया और अवैध लाभ अर्जित किया। बरामद दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों की जांच की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

दिल्ली दंगाः आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले का फैसला जुलाई में

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में फैसला टाल दिया है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने जुलाई में फैसला सुनाने का आदेश दिया। इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा हसीन ऊर्फ मुल्लाजी ऊर्फ सलमान, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम ऊर्फ बॉबी और मुंतजिम ऊर्फ मुसा को आरोपित बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 जून, 2020 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कहा गया कि 24 और 25 फरवरी, 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रुप दिया। चार्जशीट में कहा गया था कि अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी। अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के नेतृत्व में भीड़ ने खास रुप से टारगेट किया। खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई। शर्मा की हत्या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश फेंक दी। पुलिस के मुताबिक अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने पाया था कि तेज धार वाले हथियार से 51 वार के निशान हैं। ताहिर ने ही चांद बाग इलाके में भीड़ को उकसाया। चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है। दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उसके घर की छत से काफी मात्रा में हिंसा में इस्तेमाल किए गए सामान बरामद किए गए। फरवरी, 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे।

हाई कोर्ट ने रद्द किए न्यूजक्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस और ईडी के मामले

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूजक्लिक वेबसाइट और इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को विदेशों से मिले धन के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मामलों को निरस्त कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि न्यूजक्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दर्ज मामले शक्तियों का दुरुपयोग है। उच्चतम न्यायालय ने 15 मई, 2024 को प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया था।कोर्ट ने 7 जुलाई, 2021 में उच्च न्यायालय ने ईओडब्ल्यू के मामले में प्रबीर पुरकायस्थ औऱ प्रांजल पांडेय को अंतरिम जमानत दी थी। ईओडब्ल्यू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पुरकायस्थ पर आरोप था कि उनकी कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अमेरिका की कंपनी वल्र्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स कंपनी से 9 करोड़ 59 लाख रुपये की एफडीआई हासिल की। ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि ये एफडीआई कानून का उल्लंघन कर हासिल की गई। उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया था कि प्रबीर पुरकायस्थ की हिरासत लेते वक्त उनके वकील को हिरासत की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार करते वक्त गिरफ्तारी की लिखित वजह भी नहीं बताई गई। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने की वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को राजधानी में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा को लेकर बैठक की। इस बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह जानकारी सोशल मीडिय अकाउंट 'एलजी दिल्ली' पर साझा की गई है।उपराज्यपाल ने वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मरम्मत के काम में तेजी लाने और मॉनसून सीजन से पहले ही सभी वर्षा जल संचयन तंत्र पूरी तरह से चालू करने की निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साझा किया विकसित राजस्थान-2047 का रोडमैप

» 'युवा शक्ति व निवेश संवर्धन से प्रदेश बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था'

» 'किसानों की समृद्धि व महिला सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता'

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद् की 11वीं बैठक में शामिल हुए। उन्होंने राजस्थान के विकास के विजन, उपलब्धियों एवं भावी कार्ययोजना को प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता, सुशासन, नवाचार और समावेशी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा राजस्थान विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा अनुरूप राज्य सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के युवाओं की शक्ति के उपयोग के मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार प्रदेश की 63 प्रतिशत युवा आबादी को विकास का प्रमुख आधार बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

पर्यटन में बदलाव के 12 वर्षः देश में पर्यटन स्थलों पर 24 घंटे हेल्पलाइन, टूरिस्ट पुलिस व्यवस्था

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। पर्यटन में बदलाव के 12 साल के तहत देश में एक ऐसा मजबूत पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा रहा है, जहां घरेलू और विदेशी यात्री बिना किसी डर के घूम-फिर सकें।पर्यटन मंत्रालय के अनुसार सुरक्षित और स्वागत-पूर्ण यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 24 घंटे बहुभाषी हेल्पलाइन और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष टूरिस्ट पुलिस की तैनाती जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं जमीनी स्तर पर लागू की हैं। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति, शिकायत या तुरंत जानकारी के लिए सरकार ने एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1363 जारी किया है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे काम करती है। विदेशी और स्थानीय पर्यटकों की सुविधा के लिए यह सेवा 12 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि भाषा की वजह से किसी को मदद मिलने में कोई बाधा न आए। इसके अलावा, पर्यटकों को जमीनी स्तर पर तत्काल और विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में टूरिस्ट पुलिस की तैनाती की गई है। वर्तमान में यह व्यवस्था गोवा, केरल, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर सहित देश के 15 प्रमुख राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी तरह सक्रिय है। इस विशेष पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकना, पर्यटकों का मार्गदर्शन करना और उनके साथ होने वाले किसी भी दुर्व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई करना है।

सुप्रीम कोर्ट के जज ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस केस से खुद को अलग किया

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। ट्रायल कोर्ट की ओर से 217 करोड़ की वसूली मामले में आरोप तय करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने खुद को अलग कर लिया। अब इस मामले पर वो बेंच सुनवाई करेगी, जिसके सदस्य जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा नहीं होंगे। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में जैकलीन के अलावा ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉल के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने इन आरोपितों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4, भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 186, 384, 386, 388, 406, 409, 420, 468, 471 और 120बी के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदिति सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किय था। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ रुपये अदिति सिंह से लिए लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ रुपये लिये थे। ईडी ने कहा था कि सुकेश ही इस मामले का मास्टरमाइंड है। इस मामले में उसने अदिति सिंह को पहला फोन लैंडलाइन से किया था। ईडी ने कहा कि सुकेश ने बताया कि इस पैसे से गाड़ी, लग्जरी आइटम और गिफ्ट खरीदे गए।ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने के लिए उस अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है।

फोर्टिस गुरुग्राम ने मायलोमा और लिंफोमा के लिए भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया

» प्रिसीजन ब्लड कैंसर केयर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति

लोकतंत्र की शान

गुरुग्रामः फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम ने भारत में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मायलोमा एंड लिंफोमा का शुभारंभ किया है। इस पहल के माध्यम से ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए स्पेशयलाइज्ड, मरीज केंद्रित और शोध-आधारित देखभाल प्रदान की जाएगी। इस केंद्र को "सन डिजीज़ वन डॉक्टर, वन फोकस" के सिद्धांत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जहां विशेषज्ञों के अलावा एडवांस डायग्नॉस्टिक क्षमताओं, इनोवेटिव थेरेपी, प्रिसीजन मेडिसिन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, सैलुलर थेरेपी, क्लीनिकल रिसर्च तथा व्यापक मरीज सपोर्ट सेवाओं को एक ही एकीकृत प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। श्री यश रावत, सीनियर वाइस प्रेसीडेंट एवं एसबीयू हेड, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम, ने कहा, "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मायलोमा एंड लिंफोमा भारत में हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय मुकाम है जिसने एडवांस कैंसर और ट्रांसप्लांट केयर के मामले में एफएमआरआई की अग्रणी स्थिति को और मजबूती दी है। यह पहल मायलोमा तथा लिंफोमा के इलाज के लिए स्पेशयलाइज्ड उपचार की तलाश करने वाले मरीजों के लिए नेशनल रेफरल हब के तौर पर काम करने के साथ-साथ क्लीनिकल शोध, शारीरिक शिक्षा, तथा हेमेटोलॉजिक ओंकोलॉजी के क्षेत्र में देखभाल की दृष्टि से भविष्य के मानकों को तय करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।"

मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस शुरू करेगी बड़ा देशव्यापी आंदोलन

खरगे की अध्यक्षता में हुई पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक में लिया गया अहम फैसला

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः कांग्रेस ने देश में गहराते आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों और लोकतंत्र पर कुठाराघात जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर बड़ा देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में देश के मौजूदा हालात पर पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की तीन घंटे तक चली महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी और संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश समेत वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने बताया कि यह आंदोलन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सीधे उन लोगों के बीच जाएंगे जो महंगाई, बेरोजगारी तथा वर्तमान व्यवस्था से पीड़ित हैं, उनका दर्द बांटेंगे और उनकी आवाज को आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे आंदोलन का विस्तृत कार्यक्रम अगले 4-5 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि बैठक में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (रसोई गैस) के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आम जनता गंभीर संकट में है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। देश में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी और गलत नीतियों के कारण पूरा एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो चुका है। रोजगार न होने की वजह से देश का युवा अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है।

मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में आरडीजी सहित हिमाचल हितों के मुद्दे प्रमुखता से उठाए

लोकतंत्र की शान

शिमलाः मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लिया। बैठक का विषय 'विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास' था। बैठक में देशभर में समावेशी विकास सुनिश्चित करने तथा विकसित भारत के दृष्टिकोण को ठोस परिणामों में परिवर्तित करने की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के समक्ष मौजूदा वित्तीय चुनौतियों को प्रमुखता से उठाते हुए प्रधानमंत्री से राज्य के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया, जो राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान, जलविद्युत परियोजनाओं में मुफ्त बिजली के हिस्से में कमी तथा जीएसटी व्यवस्था से उत्पन्न राजस्व हानि का आकलन कर सके।

तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका, राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाईक ने दिया इस्तीफा

लोकतंत्र की शान

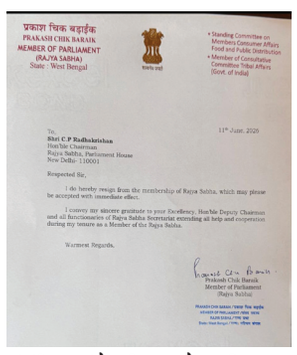

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को गुरुवार को एक और राजनीतिक झटका लगा जब पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाईक ने उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा सचिवालय को सौंपते हुए इसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का अनुरोध किया है। अपने इस्तीफा पत्र में बड़ाईक ने लिखा, "मैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, जिसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाए। मैं उपसभापति तथा राज्यसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग और सहायता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।" हालांकि, उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया है। अब राज्यसभा सचिवालय की ओर से इस्तीफे से संबंधित संवैधानिक और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। गौरतलब है कि हाल के समय में तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी और अपने संसदीय पदों से इस्तीफा दिया है। इससे पहले सांसद सुष्मिता देव और शुखेंदु शेखर रॉय ने भी राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं।प्रकाश चिक बड़ाईक के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की संख्या घटकर 10 सांसद रह गई है।

ईसीआई कार्यालय के बाहर एनएसयूआई ने किया कठपुतली प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के हजारों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) मुख्यालय की ओर विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से कठपुतलियां लेकर विरोध जताया और आयोग की स्वतंत्रता व निष्पक्षता पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि हाल के समय में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और कुछ निर्णयों ने उसकी निष्पक्षता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की मांग को लेकर बैनर और तख्तियां भी प्रदर्शित कीं। जब प्रदर्शनकारी निर्वाचन आयोग कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, तब दिल्ली पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका दायित्व नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द किए जाने सहित कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इससे यह धारणा मजबूत होती है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। विनोद जाखड़ ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पुलिस कार्रवाई के जरिए दबाने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत में लेने से लोकतांत्रिक सवालों को दबाया नहीं जा सकता और एनएसयूआई लोकतंत्र, पारदर्शिता और संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना आंदोलन जारी रखेगी।प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प की भी जानकारी सामने आई, हालांकि स्थिति को बाद में नियंत्रित कर लिया गया।

संक्षिप्त समाचार

मोदी सरकार के गौरवपूर्ण 12 वर्षः विश्वास विकास और जनकल्याण की उपलब्धि को धूमधाम से मनाएगी योगी सरकार

लोकतंत्र की शान , लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को भव्य आयोजन होगा। योगी सरकार पूरे प्रदेश में विश्वास, विकास व जनकल्याण के गौरवपूर्ण 12 वर्ष की उपलब्धि को धूमधाम से मनाएगी। मुख्यमंत्री सुबह लखनऊ व शाम को वाराणसी में होने वाले भव्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। वहीं लोकभवन में होने वाले कार्यक्रम में राजग सरकार के सहयोगी दलों (अपना दल एस, सुभासपा, राष्ट्रीय लोकदल व निषाद पार्टी) के प्रमुख/मंत्री भी मौजूद रहेंगे।

पीएम मोदी के सुशासन के 12 वर्ष की उपलब्धियों को बताएगी योगी सरकार-सुशासन को समर्पित पीएम मोदी के द्वारा 140 करोड़ भारतीयों की निरंतर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन में मीडिया संवाद करेंगे। मोदी सरकार के नेतृत्व में जनकल्याण, अवस्थापना एवं आस्था को मिले सम्मान के विषय में संपूर्ण जानकारी भी देंगे। मोदी सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा को लेकर यहां प्रदर्शनी भी लगेगी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

सरकार के साथ ही भाजपा संगठन व सहयोगी दल के नेता भी रहेंगे मौजूद- भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगठन की तरफ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष/केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी भी रहेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के मंत्री व सहयोगी दल अपना दल (एस) के आशीष पटेल, निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद, सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर व राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार भी रहेंगे।

गन्ना विकास विभाग के सहयोग से 3500 विद्यार्थियों को मिलेगी रोजगारपरक शिक्षा व प्लेसमेंट सहयोग

लोकतंत्र की शान , लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रथम चरण में सहकारी गन्ना समितियों के सहयोग से संचालित इंटर कालेजों एवं महाविद्यालयों के जर्जर भवनों को ठीक कराया गया। यहां अतिरिक्त शैक्षणिक कक्षों का निर्माण भी कराया जा रहा है। इन कॉलेजों में दी जा रही शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने युवाओं को कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने वाधवानी फाउंडेशन के "स्किल्स डेवलपमेंट नेटवर्क (एसडीएन) के साथ एमओयू किया है। इसका उद्देश्य सहकारी गन्ना समितियों के सहयोग से संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक कौशल प्रदान करना है, जिससे वे रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें।

75 से 90 घंटे का दिया जाएगा विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण- गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि प्रदेश में सहकारी गन्ना समितियों द्वारा संचालित 09 इंटर कॉलेजों/महाविद्यालयों में लगभग 15,440 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। वर्तमान परिदृश्य में उद्योगों की मांग के अनुरूप व्यावहारिक ज्ञान, संचार कौशल, तकनीकी दक्षता, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, समस्या समाधान तथा कार्यस्थल के अनुरूप व्यवहार विकसित करना भी आवश्यक है। यह एमओयू इसे ध्यान में रखकर किया गया है। प्रथम चरण में लगभग 3,500 विद्यार्थियों को 75 से 90 घंटे का विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं के समग्र विकास व कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्हें रोजगारोन्मुखी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

बहू की मौत के बाद पति समेत पांच ससुरालीजनों पर मुकदमा दर्ज

लोकतंत्र की शान : बिजनौर। स्योहारा क्षेत्र के गांव गल्लाखेड़ी में सास-बहू के विवाद के बाद आग से झुलसी महिला की दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर और ननद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात गल्लाखेड़ी निवासी मितलेश पत्नी अतर सिंह और उनकी पुत्रवधू प्रियाशी (30) पत्नी अभिकांत के बीच विवाद हो गया था। विवाद के दौरान प्रियाशी गंभीर रूप से झुलस गई थी। वहीं सास मितलेश ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मितलेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्योहारा से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दूसरी ओर प्रियाशी को पहले सीएचसी नूरपुर, फिर जिला अस्पताल बिजनौर ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया था। उपचार के दौरान गुरुवार को प्रियाशी की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। इसके बाद मृतका के भाई मनोज पुत्र किरण सिंह निवासी आलमपुर कैंच, जनपद अमरोहा ने पुलिस को तहरीर देकर ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मृतका के पति अभिकांत, ससुर अतर सिंह, सास मितलेश, देवर हरीश और ननद हिमानी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ने बदली महेन्द्र कुमार की जिंदगी

लोकतंत्र की शान : प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। इस योजना के माध्यम से युवा न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। प्रयागराज जनपद के ग्राम बांका जलालपुर निवासी महेन्द्र कुमार इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल है।

अदिति यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सपाइयों में आक्रोश, FIR की मांग

» फुरकान खान के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबाद/ बिजनौर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री Akhilesh Yadav की पुत्री Aditi Yadav के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित रूप से की गई आपत्तिजनक एवं अश्लील पोस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन में भारी रोष व्याप्त है। मामले को गंभीरता से लेते हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। सपाइयों ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर किसी महिला की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाना निंदनीय है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करने का साहस न कर सके। ज्ञापन सौंपने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा यह मामला अत्यंत गंभीर है और प्रशासन को बिना देरी किए आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

'विकसित भारत' के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा यूपीः मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान

लखनऊ/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। इसमें अनेक मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर इसे साझा भी किया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में सम्मिलित हुआ। 'विकसित भारत@ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास' की थीम पर केंद्रित इस बैठक में मानव विकास, सुशासन और जनभागीदारी को विकास की धुरी बनाकर 'विकसित भारत' के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण को विकास का आधार बनाकर 'विकसित भारत' के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, जगत प्रकाश नड्डा, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मण्डाविया समेत अनेक मंत्री व कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।

कलेक्ट्रेट सभागार में उर्वरक प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न, किसानों को समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) जनपद बरेली के कलेक्ट्रेट सभागार में आज कृषि विभाग की उर्वरक प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जनपद में किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था तथा भंडारण की वर्तमान स्थिति का विस्तृत आकलन करना रहा। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ उर्वरक आपूर्ति एवं प्रबंधन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिए कि किसानों को कृषि कार्यों के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उर्वरकों की आपूर्ति समयबद्ध, पारदर्शी और सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन को देखते हुए उर्वरकों की मांग बढ़ने की संभावना रहती है, ऐसे में पर्याप्त भंडारण और वितरण व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। समीक्षा के दौरान विभिन्न विकासखंडों एवं कृषि केंद्रों पर उर्वरकों की उपलब्धता की जानकारी ली गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी स्तर पर कृत्रिम कमी, कालाबाजारी अथवा अनियमित वितरण की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

नजीबाबाद विधानसभा 2027 की तैयारियों में जुटे फरहान खान, अखिलेश यादव से की मुलाकात

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबाद। आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के युवा नेता फरहान खान ने लखनऊ पहुंचकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे बिजनौर जनपद की राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती तथा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। फरहान खान ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की गतिविधियों और जनसमस्याओं से संबंधित मुद्दों को भी पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखा। सूत्रों के अनुसार, फरहान खान आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिलेभर में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी 2027 के चुनावों को लेकर प्रदेशभर में संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर विशेष जोर दे रही है। फरहान खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूत प्रदर्शन करेगी और प्रदेश में बदलाव का मार्ग प्रशस्त होगा। इस मुलाकात के बाद नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है तथा समर्थक इसे आगामी चुनावी तैयारियों का महत्वपूर्ण संकेत मान रहे हैं।

आंधी में नुमाइश का झूला गिरा, मां-बेटा घायल

» 11 वर्षीय बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

लोकतंत्र की शान

(बरेली उत्तर प्रदेश संदीप चंद्रा) बरेली। शहर में गुरुवार रात तेज आंधी और बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। विशप मंडल इंटर कॉलेज परिसर में लगी नुमाइश में एक झूला अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आकर मां और बेटा घायल हो गए। घटना के बाद नुमाइश परिसर में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार थाना बारादरी क्षेत्र के संजय नगर निवासी गोविंद की पत्नी ज्योति अपने 11 वर्षीय पुत्र अनमोल के साथ नुमाइश घूमने पहुंची थीं। इसी दौरान अचानक मौसम ने करवट ले ली और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मौसम खराब होने के बावजूद कुछ झूले संचालन में थे। इसी बीच तेज हवा के दबाव के कारण एक झूला असंतुलित होकर गिर गया। झूला गिरने की घटना में ज्योति और उनका पुत्र अनमोल उसकी चपेट में आकर घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए नुमाइश परिसर में भगदड़ जैसे हालात बन गए। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल महिला ज्योति का प्राथमिक उपचार किया और हालत सामान्य होने पर उन्हें घर भेज दिया गया, जबकि बच्चे अनमोल को अधिक चोट लगने के कारण डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती कर लिया गया। चिकित्सकों के अनुसार बच्चे की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

इंडियन गैस एजेंसी को मिला नया नेतृत्व, संकट के दौर से संभालने वाले प्रियंक चौधरी बने मैनेजर

लोकतंत्र की शान,खिज़र अहमद

नजीबाबाद। इंडियन गैस एजेंसी में प्रियंक चौधरी को नया मैनेजर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में एजेंसी की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं उपभोक्ता हितैषी बनेगी। जानकारों के अनुसार प्रियंक चौधरी लंबे समय से एजेंसी से जुड़े रहे हैं और जब एजेंसी विभिन्न चुनौतियों एवं संकटों का सामना कर रही थी, उस दौरान उसे सुचारु रूप से संचालित रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए एजेंसी के संचालन को मजबूती प्रदान की, जिसके चलते आज एजेंसी बेहतर स्थिति में खड़ी है। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रियंक चौधरी ने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की समस्याओं का त्वरित समाधान और सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उनकी नियुक्ति पर एजेंसी

प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया रक्तदान

लोकतंत्र की शान

बिजनौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान 'बोवी' ने स्योहारा में धर्मनंदा ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। उनके साथ भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष देशबंधु चौहान ने भी रक्तदान कर सामाजिक सेवा का संदेश दिया।< इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक और निर्णायक परिवर्तन देखे हैं। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया, जबकि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत हुई है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12 वर्षों तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान भी स्थापित किया है। धर्मनंदा ब्लड बैंक के निदेशक डॉ. शाश्वत वर्मा ने रक्तदाताओं का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को जीवनदान मिल सकता है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. मनोज वर्मा, राजीव वर्मा, डॉ. विनीत देवरा, ब्रह्मपाल सिंह, डॉ. आशिफ, अशोक कुमार, अंचल चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

रोडवेज बस स्टैंड पर अतिक्रमण का जाल, यात्रियों की सुविधा पर कब्ज़ा

» वेलफेयर सोसाइटी ने जिलाधिकारी से की तत्काल कार्रवाई की मांग

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबाद। नगर के रोडवेज बस स्टैंड के आसपास बढ़ते अतिक्रमण को लेकर अब सामाजिक संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। राधे-राधे वेलफेयर सोसाइटी ने जिलाधिकारी को शिकायत भेजकर बस स्टैंड क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोसाइटी की अध्यक्ष नीलम माहेश्वरी ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व में रोडवेज बस स्टैंड के पास तीन यात्री शेड बनवाए गए थे, लेकिन समय के साथ इन शेडों और आसपास की सार्वजनिक भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया है। हालत यह है कि यात्रियों को बैठने तक की जगह नहीं मिल रही और भीषण गर्मी में महिलाएं, बुजुर्ग तथा बच्चे खुले आसमान के नीचे खड़े रहने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अतिक्रमण के कारण बस स्टैंड क्षेत्र में आए दिन जाम की स्थिति बनती है, जिससे यात्रियों, दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हैं और सार्वजनिक सुविधाएं धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। वेलफेयर सोसाइटी ने प्रशासन से मांग की है कि रोडवेज बस स्टैंड और यात्री शेडों के आसपास से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए, सार्वजनिक स्थानों को मुक्त कराया जाए तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके और शहर को जाम की समस्या से निजात मिले।

संक्षिप्त समाचार

जमीन विवाद में घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट, महिला से छेड़खानी का आरोप, हमले का वीडियो वायरल

लोकतंत्र की शानः हाजीपुर। वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र स्थित महम्मदपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की, लूटपाट की और एक महिला के साथ छेड़खानी व दुर्व्यवहार भी किया। यह घटना 4 जून की बताई जा रही है। दर्जनों की संख्या में पहुंचे आरोपियों ने लाठी और लोहे की रॉड से घर के सदस्यों को घायल कर दिया। इसके बाद वे घर में घुस गए और लूटपाट की। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि इस दौरान घर की एक महिला के साथ छेड़खानी और दुर्व्यवहार भी किया गया। इस मामले में पीड़ित आशा देवी के बयान पर महनार थाने में पांच नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्राथमिकी 6 जून को दर्ज की गई थी। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दर्जनों लोग लाठी, डंडे और रॉड लेकर पीड़ित परिवार पर हमला करते दिख रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है।

अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त, हाजीपुर में पुलिस का एक्शन, ड्राइवर मौके से भागा

लोकतंत्र की शानः हाजीपुर। वैशाली के हाजीपुर नगर थाना पुलिस ने बुधवार को त्रिमूर्ति चौक के पास छापेमारी कर अवैध बालू से लदे दो ट्रैक्टर जब्त किए। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने खनन विभाग को सूचित किया। खनन विभाग की टीम नगर थाने पहुंची और दोनों अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों पर जुर्माना लगाया।

नगर थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह उन्हें अवैध रूप से बालू ले जाने वाले ट्रैक्टरों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों ट्रैक्टरों को पकड़ा। हालांकि, पुलिस कार्रवाई के दौरान चालक और उपचालक मौके से फरार हो गए। विदित हो कि अवैध रूप से सफेद बालू का खनन जारी है। जब्त किए गए दोनों ट्रैक्टरों को नगर थाने लाया गया है। पुलिस ने इस संबंध में खनन विभाग को जानकारी दी है। खनन विभाग के अधिकारी अब इन ट्रैक्टरों के कागजातों की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गंगा आरती, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हुए शामिल, पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर मंगल कामना कार्यक्रम

लोकतंत्र की शानः हाजीपुर। वैशाली के हाजीपुर स्थित कोनहारा घाट के नमामि गंगे घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गंगा आरती और मंगल कामना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधिवत पूजा-अर्चना के साथ गंगा आरती का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मां गंगा से देश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। कार्यक्रम में हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह, भाजपा वैशाली दक्षिणी के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा, नगर परिषद हाजीपुर की सभापति डॉ. संगीता कुमारी, उपसभापति कंचन कुमारी और कार्यापालक पदाधिकारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नमामि गंगे घाट पर आयोजित इस गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और दीपों की जगमगाहट ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान देश की उन्नति और समाज के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिससे पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से भर गया।

3 दिन तक बारिश की संभावना, जिले में 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, मोबाइल पर मिला अलर्ट

लोकतंत्र की शानः मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में गुरुवार की सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह तेज धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन करीब 7 बजे के बाद काले बादल छा गए और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली, हालांकि उमस बरकरार रही। इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक जिले में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई है। सुबह बारिश शुरू होने से पहले ही मौसम विभाग की ओर से लोगों के मोबाइल फोन पर अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट में अगले कुछ घंटों के दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और गरज के साथ बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला और कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। बुधवार को भी जिले के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई थी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। हालांकि दोपहर में हुई हल्की बारिश के बाद उमस बढ़ जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सुबह के समय हवा में नमी की मात्रा 85 प्रतिशत और दोपहर में 75 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं वाष्पीकरण की दर सामान्य से लगभग चार गुना अधिक 8.5 मिलीमीटर रही। पूरे दिन पछुआ हवा करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रही। पूसा स्थित ग्रामीण कृषि मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि मानसून तेजी से उत्तर बिहार की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से जिले में मानसून पूर्व गतिविधियां तेज हो गई हैं और बारिश की संभावना लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं और पछुआ हवा के प्रभाव के कारण वातावरण में नमी अधिक बनी हुई है, जिससे उमस का असर महसूस किया जा रहा है। डॉ. सत्तार ने संभावना जताई कि अगले सप्ताह तक मानसून मुजफ्फरपुर जिले में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिले में अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। ऐसे में बीच-बीच में बारिश होने के बावजूद लोगों को गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

चूल्हे की चिंगारी से गैस सिलेंडर ब्लास्ट, खाना बना रही थी महिलाएं, अगलगी में 4 भाइयों के 2 घर राख

लोकतंत्र की शानः मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाके में दो घर जल गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, घर शिवनाथ राम, जयकरण राम, नागेंद्र राम और जगुदार राम का था। ये चारों भाई अपने संयुक्त परिवार के साथ इन्हीं दो घरों में रहते थे। घटना के समय घर की महिलाएं खाना बना रही थीं। इसी दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से आग फैल गई। इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। परिजनों की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत पानी और बालू डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि, आग की लपटें काफी तेज थी। ग्रामीणों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। करीब 5 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना करजा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की है। घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन और अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गए। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। करजा थाना के थानेदार परमहंस कुमार ने बताया कि प्रतापपुर गांव में आग लगने से 2 घर जल गए हैं। एक सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ था। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और पुलिस प्रशासन मामले में आगे की कार्रवाई कर रहा है।

जनकल्याण शिविर में आयुष्मान, उद्यमी, किसान सहित कई योजनाओं का मिलेगा लाभ

लोकतंत्र की शानः मो. जियाउद्दीन

सहरसाः जिले में आयोजित होने वाले सहयोग सह जनकल्याण शिविर में विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इन शिविरों में विशेष रूप से स्वास्थ्य, स्वरोजगार, किसान, श्रमिक, दिव्यांग एवं बालिका कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राशन कार्डधारी सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का निशुल्क इलाज सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत केवल आधार कार्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत युवाओं को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 5 लाख अनुदान एवं 5 लाख ब्याजमुक्त ऋण शामिल है। साथ ही उद्यमिता प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए आधार, बैंक खाता एवं भूमि रिकॉर्ड आवश्यक होते हैं। निर्माण श्रमिकों के लिए बीओसीडब्ल्यू (BOCW) निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से दुर्घटना सहायता, चिकित्सा सुविधा, मातृत्व लाभ, बच्चों की शिक्षा, विवाह सहायता, पेंशन एवं आवास निर्माण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य है। दिव्यांगजन के लिए यूडीआईडी (UDID) कार्ड योजना के तहत एक विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया जाता है, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। वहीं, एडीआईपी (ADIP) योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाते हैं।

गंगा तटों की सुरक्षा से संबंधित कार्यों को एक माह में पूरा करने का निर्देश

लोकतंत्र की शानः पटना

जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने आज भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जवनिया गांव में गंगा नदी के तट पर चल रहे कटाव निरोधी कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता तथा बाढ़ पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

सचिव ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं की जानकारी ली तथा चल रहे कार्यों पर उनका फीडबैक प्राप्त किया। ग्रामीणों ने गंगा नदी के निरंतर कटाव से उत्पन्न चुनौतियों को साझा करते हुए कटाव निरोधी एवं संरक्षण कार्यों के प्रति संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित गंगापुर, भुसौला, नन्दपुर एवं दामोदरपुर (जवनिया) गाँवों को कटाव से सुरक्षित रखने के लिए लगभग 1200 मीटर लंबाई में कटाव निरोधी कार्य कराया जा रहा है। इस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति राशि 52.56 करोड़ है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। डॉ. सिंह ने कार्यों में तेजी लाते हुए कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया, साथ ही कहा कि मानसून की संवेदनशीलता को ध्यान में रख कर सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा कटाव निरोधी कार्यों को हर हाल में अगले एक माह के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने अभियंताओं एवं संवेदकों को कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य संपन्न करने का निर्देश दिया। सचिव ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के गंगापुर, भुसौला, नन्दपुर एवं जवनिया सहित आसपास के गाँवों को गंगा नदी के कटाव से प्रभावी सुरक्षा मिलेगी तथा स्थानीय आबादी एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।

यह मेरा नहीं बल्कि बिहार के लोकगीतों का सम्मान: मनीषा श्रीवास्तव

लोकतंत्र की शान

पटनाः सुप्रसिद्ध लोकगायिका मनीषा श्रीवास्तव को संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 देने की घोषणा हुई है। यह बिहार के लिए गौरव का विषय है।

इस सम्बन्ध में हिन्दुस्थान समाचार से विशेष बातचीत में मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि बिहार की लोकगीतों, लोक संस्कृति के साथ-साथ उन तमाम कलाकारों का है, जो मेरी तरह बिहार के परम्परागत विषयों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसको सहेजने एवं संवारने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस सम्मान को अपने बड़े बुजुर्गों, गुरुजनों, साथियों को समर्पित करती हूँ। जिन्होंने मुझे हर समय प्रोत्साहन भरे शब्दों से सराहा तथा निरंतर बेहतरीन कार्य करते रहने की प्रेरणा दी।

मनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि उनका जीवन लोक संगीत को समर्पित है। उन्होंने अबतक भोजपुरी के अलावे मैथिली, अवधी, हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं में गीत गाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी बिहार की अन्य भाषाओं, अंगिका, बज्जिका एवं मगही की लोकगीतों को भी गाने की चल रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी भाषाएँ मां समान हैं और उन सभी भाषाओं में अगर अच्छे लोकगीत हैं, लोक संगीत है तो उसे उसका सम्मान मिलना चाहिए।

उन्होंने बताया कि लोकगीतों के साथ साथ बिहार के सांस्कृतिक विरासत समेत धरहोरों के ऊपर काम कर रही हैं। बाबू वीर कुँवर सिंह की जीवनी गीत, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद की जीवनी गीत, प्रधानमंत्री के मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के आह्वान को प्रेरित करता मिलेट्स गीत तथा बेटी बाचाओ एवं बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक बनाने हेतु बेटियों के ऊपर अलग-अलग विषय को लेकर गीत गा चुकी हैं। आने वाले वर्षों में बिहार के अन्य धरोहरों पर आपको गीत सुनने को मिलेंगे।

मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि शुरु से अपना अलग राह बनाकर चलती रही हूँ। मैंने बाजार के अधीन खुद को नहीं किया, बल्कि बाजार में बजने वाले गीतों के समकक्ष श्लील गीतों का एक समानांतर लकीर खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि संगीत नाटक अकादमी से मिला सम्मान उन्हें नई ऊर्जा देगा।

डीबीटी के माध्यम से करोड़ों की पेंशन राशि का हस्तांतरण, लाभार्थियों में खुशी की लहर

लोकतंत्र की शानः मो. जियाउद्दीन

सुपौलः आज दिनांक 10 जून 2026 को माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत राज्य भर के 94,29,698 लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपये की पेंशन राशि का सफलतापूर्वक अंतरण किया गया। इस अवसर पर राज्य भर में कुल 10,96,44,46,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई। इसी क्रम में सुपौल जिले के कुल 2,37,378 लाभार्थियों को 27,23,42,600 रुपये की पेंशन राशि का अंतरण किया गया। योजनावार आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 1,55,746 लाभार्थियों को 18,15,41,400 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 44,619 लाभार्थियों को 4,92,55,300 रुपये, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 10,454 लाभार्थियों को 1,19,04,400 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 12,313 लाभार्थियों को 1,37,50,000 रुपये, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के 13,516 लाभार्थियों को 1,50,85,200 रुपये तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 730 लाभार्थियों को 8,06,300 रुपये की राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर सुपौल जिला मुख्यालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन हस्तांतरण का सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक पेंशनधारियों की उपस्थिति रही।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण नहीं होगा बर्दाश्त: जिलाधिकारी

लोकतंत्र की शानः मो. जियाउद्दीन

सहरसाः सहरसा जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात सुरक्षा, अवैध अतिक्रमण और अवैध वाहन पार्किंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106, 107 एवं 327E के किनारे अवैध रूप से खड़े ट्रकों एवं अन्य वाहनों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाने तथा अर्थदंड लगाने का निर्देश संबंधित थाना पुलिस एवं परिवहन विभाग को दिया। लंबे समय से सड़क किनारे खड़े वाहनों को चिन्हित कर जब्त करने की भी बात कही गई। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के आरओडब्ल्यू (Right of Way) क्षेत्र के 15 मीटर के भीतर बने होटल, दुकान, मकान सहित अन्य अवैध संरचनाओं की पहचान कर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। नोटिस लेने से इनकार करने पर संबंधित स्थल पर चस्पा कर फोटोग्राफिक साक्ष्य सुरक्षित रखने को कहा गया। अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी है। इसके लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स और डेडिकेटेड हाईवे सर्विस टीम का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित वाहन जांच अभियान चलाने और अवैध पार्किंग के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आवश्यकतानुसार जुर्माना और प्राथमिकी दर्ज कर वाहन जब्त किए जाएंगे।

पटना में गिग वर्कर्स के लिए बन रहे एसी लाउंज

लोकतंत्र की शानः पटना

पटना में डिलीवरी बॉयज, कूरियर बॉयज, ऑटो और बाइक राइडर्स को जल्द ही गर्मी से राहत मिलेगी। पटना नगर निगम द्वारा गिग वर्कर्स के लिए शहर में दो एसी लाउंज तैयार किए जा रहे हैं। गांधी मैदान गेट नंबर- 4 और इनकम टैक्स गोलंबर के पास इसका निर्माण हो रहा है। चेन्नई के तर्ज पर इस प्री-फैब्रिकेटेड एसी लाउंज को बनाया जा रहा है, जहां आम लोग भी आराम कर सकेंगे। पिछले महीने ही नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसके निर्माण के निर्देश दिए थे।

एक साथ करीब 15 लोगों के बैठने की व्यवस्थाः इन लाउंज में एक साथ करीब 15 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। दोनों लाउंज में 30 लोग बैठ सकेंगे। नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर शुरू की गयी इस योजना का निर्माण कार्य पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

इन दोनों आश्रय स्थलों का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है और वर्तमान में फिनिशिंग का काम चल रहा है। अगले चार दिनों में यानी रविवार तक बुनियादी ढांचा पूरी तरह तैयार कर लिया जायेगा, जिसके बाद एसी लगाने और कुर्सियां बिछाने का काम पूरा होगा। 15 जून से इसे आम जनता और गिग वर्कर्स के लिए खोल दिया जाएगा।

100 एकड़ में 574 करोड़ से बनेगा डुमरी स्पोर्ट्स सिटी

लोकतंत्र की शानः पटना

बिहार में 100 एकड़ में डुमरी स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण होगा। इस परियोजना में 574 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसका प्रस्ताव जिला पदाधिकारी और जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को भेजा जा चुका है। इस प्रोजेक्ट के बेहतर इमप्लिमेंटेशन के लिए दो अलग-अलग टीमों द्वारा अहमदाबाद और ओडिशा के खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडलों का अध्ययन किया गया है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की।

डुमरी स्पोर्ट्स सिटी बिहार के खेल विकास का नया केंद्रः खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि, डुमरी स्पोर्ट्स सिटी बिहार के खेल विकास का नया केंद्र बनेगी। भविष्य में इसके आसपास खेल, प्रशिक्षण, खेल उद्योग और अन्य सहायक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं विकसित होंगी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अरवल, मधेपुरा और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस संचालन 15 जून से शुरू कर दिया जाएगा। इन केंद्रों में कबड्डी, बैडमिंटन और ताइक्वांडो खेलों का आवासीय प्रशिक्षण संचालित होगा। इसके अतिरिक्त सिवान, मुंगेर और जमुई में फुटबॉल खेल के उत्कृष्टता केंद्र विकसित किए जाएंगे।

खिलाड़ियों का चयन, प्रशिक्षकों की पहचान पूरीः बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रन शंकरण ने बताया कि, 'इन केंद्रों के लिए खिलाड़ियों का चयन और प्रशिक्षकों की पहचान पूरी कर ली गई है। उन केंद्रों का संचालन प्रारंभ करने की सभी तैयारियां पूरी हैं।' खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि, 'डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के माध्यम से ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।' विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि 30 सितंबर 2026 तक राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाएं।

BCCI के सेलेक्टेड बिहारी खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरीः इस बैठक में पंचायत स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत स्पोर्ट्स क्लबों के सक्रियकरण की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बैठक में खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ-साथ BCCI द्वारा चयनित भारतीय पुरुष और महिला वरिष्ठ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भी सामान्य प्रशासन विभाग एवं खेल विभाग की "मेडल लाओ, नौकरी पाओ" योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर ऐसे खिलाड़ियों को लेवल-9 की सरकारी नौकरियों का लाभ मिल सकेगा।

राजगीर में भारत-न्यूजीलैंड रग्बी सीरीज का आयोजनः राज्य के खेल कैलेंडर की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नवंबर 2026 में राजगीर में भारत-न्यूजीलैंड रग्बी सीरीज का आयोजन प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जुलाई-अगस्त 2026 में खेलो इंडिया अस्मिता जोनल महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता, 7 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस तथा दिसंबर 2026 में एफआईएच प्रो लीग के आयोजन की तैयारियां भी चल रही हैं।

निर्माण कार्य में विलंब पर एजेंसी पर होगी कार्रवाईः प्रगति यात्रा के अंतर्गत स्वीकृत खेल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि, 'जिन एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब किया जाएगा, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में बिहार सरकार की प्रस्तावित स्पोर्ट्स एक्शन प्लान पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिसे मुख्यमंत्री के माध्यम से नीति आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

खेल विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि, 'राज्य में 4,818 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापना की जा चुकी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लगभग 17,000 शिक्षकों को विद्यालयी बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त योग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।' उन्होंने आगे बताया कि, 'प्रस्तावित स्पोर्ट्स एक्शन प्लान में विद्यालयों के लिए फिजिकल लिटरेसी रिपोर्ट कार्ड, वैज्ञानिक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम, प्रशिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के प्रमाणन कार्यक्रम, फिट कैंपस चैलेंज, खिलाड़ियों एवं बच्चों के लिए एकीकृत वेलनेस पोर्टल, खेल विनिर्माण हब तथा डोपिंग संबंधी जागरूकता कार्यक्रम जैसी पहल शामिल हैं।'

संक्षिप्त समाचार

कटनी में कपड़ा व्यापारी पर चाकू से हमला घायल अवस्था में पहुंचाया गया अस्पताल

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, कटनी। शहर के पाठक वार्ड क्षेत्र में गुरुवार शाम एक कपड़ा व्यापारी पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में व्यापारी घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहम्मद हनीफ (57 वर्ष), निवासी पाठक वार्ड क्रमांक 57 एवं सुमालिया हैंडलूम के संचालक, गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे अपने गोदाम से घर लौट रहे थे। इसी दौरान घर के पास ही कुनाल वंशकार पिता संतोष वंशकार ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना से पहले किसी बात को लेकर रोशन ठाकुर के साथ विवाद हुआ था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसी विवाद के बाद हुए घटनाक्रम में मोहम्मद हनीफ पर हमला किया गया। चाकू लगने से वे घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है तथा हमले के पीछे के कारणों और विवाद की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति भी निर्मित हो गई थी, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है।

स्वर्णगरीआंशिक रद्द,लीलण एक्सप्रेस लेट,पुरी एक्सप्रेस बहाल

लोकतंत्र की शान : मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। उत्तर पश्चिम रेलवे पर चल रहे निर्माण और तकनीकी कार्यों के कारण आगामी दिनों में तीन रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इनमें एक ट्रेन आंशिक रद्द रहेगी,एक रीशेड्यूल होकर चलेगी, जबकि एक पूर्व घोषित प्रभावित ट्रेन को बहाल कर दिया गया है। जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि राईका बाग-जैसलमेर रेलखंड पर तिंवरी-ओसियां स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 42 और 44 पर गर्डर लॉन्चिंग कार्य किया जाएगा। इसके चलते गाड़ी संख्या 12249 शकूरबस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस 13 जून को शकूरबस्ती से चलकर केवल जोधपुर तक ही पहुंचेगी। ट्रेन का जोधपुर-जैसलमेर खंड आंशिक रूप से रद्द रहेगा। वहीं डेगाना-फुलेरा रेलखंड के नावां सिटी स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण गाड़ी संख्या 12467 जैसलमेर-जयपुर लीलण सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 जून को जैसलमेर से एक घंटे देरी से रवाना होगी। उधर यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में बिलासपुर-चांपा सेक्शन पर तीसरी-चौथी लाइन और ऑटो सिग्नलिंग का प्रस्तावित कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में गाड़ी संख्या 20814 जोधपुर-पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 13 जून को अपने तय मार्ग और समय के अनुसार सामान्य रूप से चलेगी।

मेड़तारोड में आज से 15 जुलाई तक लगेंगे वार्डवार शहरी सेवा शिविर

आमजन को मिलेगा योजनाओं का त्वरित लाभ

लोकतंत्र की शान : मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपखंड मेड़ता के शहरी क्षेत्र मेड़तारोड में 12 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक वार्डवार शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए पात्र नागरिकों को मौके पर ही त्वरित राहत एवं लाभ प्रदान करना है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आमजन को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा। शिविरों के सफल संचालन एवं समन्वय के लिए नगरपालिका मेड़तारोड के अधिशाषी अधिकारी हरेंद्र चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी को शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है, ताकि अधिकाधिक पात्र नागरिकों तक योजनाओं की जानकारी पहुंच सके और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। शिविरों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, नगरीय विकास, जलदाय, विद्युत, चिकित्सा एवं अन्य विभागों से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन का मानना है कि इन शहरी सेवा शिविरों के आयोजन से आमजन की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान होगा तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मेड़तारोड शहरी क्षेत्र में इन शिविरों का आयोजन वार्डवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा, जिसकी विस्तृत सूचना अलग से जारी की जाएगी।

80 वर्षीय बुजुर्ग को पांचों बेटों ने दिया भरण-पोषण की राशि

एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने दिलाई राशि

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के चुरहट क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने समाज को आईना दिखाने का काम किया है। जीवन भर की कमाई और संपत्ति पुत्रों के नाम करने के बाद जब 80 वर्षीय वृद्ध चन्द्रभान साहू को ही उनके बेटों ने सहारा देने से इनकार कर दिया, तब प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब पांचों बेटों ने बुजुर्ग चन्द्रभान साहू को एक-एक हजार रुपए की राशि नायब तहसीलदार की मौजूदगी में दिया है। बुजुर्ग चंद्रभान साहू अब अपने घर में रहने लगे हैं और उनके चेहरे में खुशी की झलक साफ देखी जा सकती है। ग्राम पटपरा निवासी चन्द्रभान साहू ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के तहत एसडीएम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति पुत्रों के नाम कर दी थी, लेकिन वृद्धावस्था में कोई भी उनकी देखभाल नहीं कर रहा है। भोजन, दवा और दैनिक जरूरतों के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें अपना घर छोडक़र नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने को मजबूर होना पड़ा। मामले को गंभीरता से लेते हुए चुरहट एसडीएम विकास कुमार आनंद ने प्रकरण दर्ज कर जांच कराई और सभी बेटों को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार रामजियावन साहू, शिवमूर्ति साहू, लखपति साहू एवं हिन्दपति उर्फ छोटई साहू अपने पिता को प्रतिमाह 1-1 हजार रुपये, जबकि धनपति उर्फ गोलई साहू 2 हजार रुपये प्रतिमाह देंगे। इस प्रकार चन्द्रभान साहू को हर महीने कुल 6 हजार रुपये भरण-पोषण राशि प्राप्त होगी।

थाना विजयराघवगढ़ की अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही, ट्रैक्टर-ट्राली जप्त

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में जिले में अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में एस डी ओ पी महोदय विजयराघवगढ़ वीरेंद्र धार्वे के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के नेतृत्व में विजयराघवगढ़ पुलिस द्वारा अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। थाना विजयराघवगढ़ पुलिस को ग्राम खेरवा घाट के पास एक ट्रैक्टर-ट्राली में रेत भरे होने की सूचना प्राप्त हुई भरी रेत को अवैध रूप से परिवहन किया जाना पाए जाने पर पुलिस द्वारा मौके पर गवाहों के समक्ष बिना नंबर के सोनालीका कंपनी के नीले रंग के ट्रैक्टर ट्राली को रेत सहित जप्त किया गया। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। जप्तशुदा ट्रैक्टर-ट्राली को सुरक्षार्थ थाना विजयराघवगढ़ परिसर में खड़ा कराया गया है तथा वाहन के विरुद्ध धारा 106 बी.एन.एस. एस. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है। विशेष भूमिका - इस कार्यवाही में थाना प्रभारी श्री अभिषेक चौबे , उपनिरी . शैलेंद्र सिंह प्रधान आरक्षक मुकेश सिंह, आरक्षक पप्पू प्रजापति की विशेष भूमिका रही।

नागौर पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियानः 9 मामले दर्ज, 6 आरोपी गिरफ्तार, 847 पव्वे शराब जब्त

लोकतंत्र की शान

नागौर/ मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर आशाराम चौधरी के निर्देशन में जिलेभर में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। वृत्ताधिकारी नागौर जतिन जैन के नेतृत्व में गठित विभिन्न पुलिस टीमों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध शराब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। इस अभियान में सदर नागौर, गोटन, जंसनगर, खाटूबड़ी, जायल, सुरपालिया सहित डीएसटी टीम को शामिल किया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 9 प्रकरण दर्ज किए गए तथा 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियान के दौरान 847 पव्वे अवैध देशी शराब, 73 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब, 92 बीयर बोतलें तथा 2 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की हैं। मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने झाडीसरा निवासी महेन्द्रसिंह पुत्र करणीसिंह राजपूत (23 वर्ष) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 128 पव्वे अवैध देशी शराब एवं 8 बीयर बोतलें बरामद कीं तथा गोटन थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुनाराम पुत्र उमाराम मेघवाल तथा रामअवतार पुत्र भूराराम बावरी को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से क्रमशः 55 एवं 60 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद की गई।इसी प्रकार

आधार सेवाओं को मिलेगा नया आयामः नागौर में 127 ऑपरेटर्स को UIDAI ने दिया विशेष प्रशिक्षण

लोकतंत्र की शान

नागौर/ मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। आधार सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को जिला परिषद सभागार में आधार ऑपरेटर्स एवं सुपरवाइजर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिलेभर से आए 127 आधार ऑपरेटर्स एवं सुपरवाइजर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आधार नामांकन और अद्यतन प्रक्रियाओं से जुड़े नवीनतम तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधार सेवाओं में होने वाली त्रुटियों को कम करना, तकनीकी दक्षता को बढ़ाना तथा UIDAI द्वारा निर्धारित सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना रहा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आधार नामांकन की प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन, बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण, सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा नवीन तकनीकी अपडेट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षक खेमराज सिंह, केंद्र प्रबंधक आधार सेवा केंद्र (ASK) जोधपुर तथा भोमसिंह चौहान, केंद्र प्रबंधक आधार सेवा केंद्र (ASK) नागौर ने ECMP (Enrollment Client Multi Platform) प्रणाली की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्यों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और गुणवत्ता सुधार के उपायों की जानकारी साझा की। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

कागजों में वितरित 124 ट्रैक्टर ऋण घोटाले की जांच में झोलझाल

- कलेक्टर के निर्देश पर भी नहीं मिल सका जांच प्रतिवेदन
- एडीएम की अध्यक्षता में गठित की गई है जांच टीम

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सीधी की शाखा गांधीग्राम में 124 ट्रैक्टर ऋण घोटाले की जांच का प्रतिवेदन समय सीमा व्यतीत होने के बाद भी न मिलने से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ट्रैक्टर घोटाले की जांच को लेकर चर्चा होने लगी है कि फिर से मामला दब चुका है। कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच में उस दौरान चालानी कार्रवाई की गई थी। अब मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा है कि एक जन प्रतिनिधि ने लाखों में सौदा कर मामले को रफा-दफा कराने की दम भरा है। गौरतलब है कि कलेक्टर विकास मिश्रा के आदेश पर फिर जांच शुरू तो हुई लेकिन निर्धारित तिथि 8 मई 2026 के बीतने के महीने भर बाद भी जांच प्रतिवेदन नहीं मिल सका है। दरअसल ट्रैक्टर ऋण घोटाले की जांच को पूर्ण करना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ट्रैक्टर ऋण घोटाला के सामने आने के बाद से गठित टीमों के पूर्व में चार एडीएम बदल चुके हैं लेकिन निर्धारित तिथि तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ। कारण घोटाले से जुड़े कई दस्तावेजों को ही बैंक स्तर से गायब करा दिया गया है। लिहाजा गठित टीम को जांच पूरी करने के लिए संबंधित कागजात ही नहीं मिल पा रहे हैं। उच्च स्तर पर ट्रैक्टर घोटाले की जांच को दबाने का प्रयास सालों से किया जा रहा है। ट्रैक्टर ऋण घोटाले का मामला वर्तमान कलेक्टर विकास मिश्रा के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा जांच के लिए अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय को जांच टीम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं जांच टीम के सदस्य में एसडीएम गोपद बनास राकेश शुक्ला, डीएसपी मुख्यालय अमन मिश्रा, गोपद बनास तहसीलदार राकेश शुक्ला, वरिष्ट सहकारी निरीक्षक मदन सिंह उइके एवं वरिष्ट सहकारी निरीक्षक एसपी पाण्डेवा को शामिल किया गया। बताते चलें कि दो करोड़ से ऊपर का ट्रैक्टर घोटाला तीन वर्ष पूर्व सामने आने पर तत्कालीन कलेक्टर द्वारा छः सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित की गई थी। उस दौरान सात दिवस में जांच प्रतिवेदन देने के आदेश दिए गए थे। अपर कलेक्टर के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने उस दौरान भी सदस्य एसडीएम गोपद, डीएसपी, तहसीलदार गोपद बनास, सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग सीधी, वरिष्ट सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग सीधी को शामिल किया गया था। टीम द्वारा अपनी जांच शुरू भी की गई लेकिन उसका जांच प्रतिवेदन सामने नहीं आया है। कारण टीम द्वारा जांच का दायरा ज्यादा बताते हुए इस पर अपनी जांच कागजों में ही जारी रखी गई जिसके चलते जांच प्रतिवेदन सामने नहीं आया। बाद में उच्च स्तरीय दबावों के चलते इस घोटाले की फाइल को ठंडे बस्ते में कैद करा दिया गया। अब कलेक्टर विकास मिश्रा की जानकारी में यह ट्रैक्टर घोटाला सामने आया तो उनके द्वारा फिर से जांच टीम अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कर 8 मई 2026 तक मांगा गया था। यह समय भी बीत चुका है।

मोहनिया से रात भर निकल रही अवैध रेत

सोन घड़ियाल एवं कोतवाली पुलिस का मिल रहा संरक्षण

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। कोतवाली थाना अंतर्गत देवघटा गांव के मोहनिया खदान से रात भर सोन नदी से अवैध रूप से रेत निकालने का सिलसिला चल रहा है। रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में पांच गाडिय़ों के संलिप्त होने की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दी गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सोन घडिय़ाल के पिपरोहर बीट के मुंशी की सहमति पर रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन सोन नदी से चल रहा है। यदि कोई ग्रामीण रेत के अवैध कारोबार की सूचना संबंधित अधिकारियों को देता है तो उसकी जानकारी बीट मुंशी द्वारा रेत कारोबारियों तक पहुंचा दी जाती है। बताया गया है कि संबंधित एक कर्मचारी द्वारा अधिकारियों की सांठ-गांठ से रेत का अवैध कारोबार संचालित कराया जा रहा है। सोन घडिय़ाल अभ्यारण्य का यह कर्मचारी सीधी के साथ ही सिंगरौली जिले में भी रेत का अवैध कारोबार संचालित कराया जा रहा है। सिटी कोतवाली में पदस्थ एक आरक्षक भी रेत के काले कारोबार में सहभागिता प्रदर्शित कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 12वां संस्करण दिव्य एवं भव्य रूप में होगा आयोजित : श्रवण शुक्ला

- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का चल रहा प्रयास

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 के 12वें संस्करण को इस वर्ष देशभर में विशेष रूप से मनाया जाएगा। जिला सांस्कृतिक प्रभारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध श्रवण शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित होगा। आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित इस वर्ष की थीम "स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग" है, जिसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में भी स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवनशैली को बढ़ावा देना है। सीधी जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को दिव्य एवं भव्य स्वरूप देने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की अनूठी पहल–श्रवण शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष का योग दिवस कई मायनों में विशेष है। आयुष मंत्रालय द्वारा 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 बजे से 7:35 बजे तक विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन योग सत्र के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके माध्यम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जिले के योग साधकों एवं नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इच्छुक व्यक्ति आयुष योग संगम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं अथवा 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और पूरे वर्ष नियमित अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए "योग 365" जैसी पहल भी संचालित की जा रही हैं।

रामकृष्ण परमहंस वार्ड में दो विकास कार्यों का भूमिपूजन गरिमामय वातावरण में संपन्न

- महापौर, क्षेत्रीय पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ विकास कार्यों का शुभारंभ

लोकतंत्र की शान

कटनी : शहर के रामकृष्ण परमहंस वार्ड में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नगर निगम कटनी द्वारा लाखों की लागत से दो निर्माण कार्यों का भूमिपूजन महापौर प्रीति संजीव सूरी, क्षेत्रीय पार्षद शकुंतला सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में गरिमामय वातावरण में संपन्न किया गया। कार्यक्रम में मेयर इन काउंसिल सदस्य सर्वश्री डॉ. रमेश सोनी, सुभाष साहू, जयनारायण निषाद, बीना बैनर्जी, पार्षद सीमा श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष कौशलेश मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

इन विकास कार्यों का हुआ शुभारंभ–भूमिपूजन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण विकास कार्यों की शुरुआत की गई, जिनमें साहू हाउस से कबाड़ी मेन रोड तक लगभग 17.60 लाख रुपये की लागत से सी.सी. रोड निर्माण कार्य तथा बिलगवां रोड पर 4.46 लाख रुपये की लागत से रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य शामिल है। इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में आवागमन व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा बारिश के समय होने वाली समस्याओं से नागरिकों को राहत मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर श्रीमती सूरी ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य हर वार्ड में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, रिटेनिंग वॉल और सीसी रोड जैसे कार्यों से शहर की तस्वीर बदल रही है और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। क्षेत्रीय पार्षद शकुंतला सोनी ने कहा कि वार्ड में लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कराया जा रहा है। उन्होंने महापौर एवं नगर निगम प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी क्षेत्र में विकास कार्यों की गति तेज रहेगी और हर समस्या का समाधान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। भूमिपूजन उपरांत महापौर श्रीमती सूरी एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने वार्ड का भ्रमण करते हुए स्थानीय नागरिकों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा प्रभावी निराकरण का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा सामूहिक पौधारोपण किया जाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल के सत्तारूढ़ दल के संसदीय उपनेता ने ही संसद में की सरकार की आलोचना

काठमांडू। सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के संसदीय दल के उपनेता विपिन आचार्य ने सदन में गुरुवार को कहा कि सरकार संसद की गरिमा को कम करने का काम कर रही है। संसद के 'शून्य समय' में उन्होंने कहा कि सांसदों के गंभीर मुद्दों की भी सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतिनिधि सभा में सांसद जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। आरएसपी के सह-महामंत्री आचार्य ने कहा कि यदि शून्य समय में हमारे द्वारा उठाई गई बातें सुनी जाती हैं, दर्ज की जाती हैं और उन्हें कार्यान्वयन की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जाता है, तो इसे शून्य समय नहीं बल्कि 'पूर्ण समय' कहा जाना चाहिए। लेकिन यदि जनता की पीड़ा और सांसदों के सवाल बोलने के बाद भी शून्य में ही विलीन हो जाते हैं, तो इसका नाम 'ब्लैक होल समय' रख देना चाहिए।" उन्होंने 'ब्लैक होल' का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार ब्लैक होल में प्रकाश तक गायब हो जाता है, उसी तरह संसद में नागरिकों की आवाज, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और सरकार की जिम्मेदारी भी गायब नहीं होनी चाहिए। आचार्य ने कहा, "शून्य समय वह संवैधानिक द्वार है, जिसके माध्यम से जनता की पीड़ा संसद तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद आगे बढ़ने का रास्ता भी होना चाहिए। सांसद बोलते रहें, सरकार न सुने, जनता आवाज उठाती रहे और व्यवस्था मौन बनी रहे—यह परंपरा अब समाप्त होनी चाहिए।

नेपाल से भारत ले जाया जा रहा 922 किलोग्राम गांजा बरामद

काठमांडू। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) ने आज सुबह देश से भारत ले जाया जा रहा 922 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। यह बरामदगी मोरंग जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के जहदा से हुई है। सशस्त्र पुलिस बल, नेपाल सीमा सुरक्षा बल के सोमबारी बीओपी, नोचा तथा तरेगामा पोस्ट से खटाई गई संयुक्त टोली ने इस संबंध में पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है। यह गांजा 29 पैकेटों में धान की भूसी की बोरियों के नीचे छुपाकर पिकअप में रखा गया था। एपीएफ के अनुसार, पिकअप के एक मोटरसाइकिल (बीआर 38 जेड 7452) आगे चल रही थी। सुरक्षा कर्मियों को देखते ही दोनों चालक अपने वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए।

भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के अवशेष मप्र के सांची में फिर किए जाएंगे स्थापित

नई दिल्ली। भगवान बुद्ध के दो सबसे प्रमुख और प्रिय शिष्यों- अर्हंत सारिपुत्र और अर्हंत मौद्गल्यायन के पवित्र बौद्ध अवशेषों को मंगोलिया की 10 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची ले जाया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये पवित्र अवशेष मूल रूप से सांची के स्तूपों में ही संरक्षित हैं, जहां इन्हें एक बार फिर पूरे राजकीय और धार्मिक सम्मान के साथ पुनः स्थापित किया जाएगा।

इससे पहले बुधवार को भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से पवित्र अवशेषों को मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर से दिल्ली वापस लाया गया। दिल्ली आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आज अवशेषों की रवानगी के दौरान अभिनेत्री एवं लोकसभा सदस्य कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हवाई अड्डे पहुंचकर अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की। इस यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी पवित्र अवशेषों के साथ उपस्थित रहे। नेताओं ने कहा कि इस यात्रा ने भारत और मंगोलिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान की है। इन पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी मंगोलिया के गंडन तेगचेनलिंग मठ के विशेष अनुरोध पर आयोजित की गई थी। संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय ने मध्य प्रदेश सरकार, श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी और आईबीसी के सहयोग से 31 मई से 9 जून तक इस सफल प्रदर्शनी का संचालन किया। मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आम जनता के लिए खोली गई इस प्रदर्शनी में जनसैलाब देखने को मिला। लगभग 34 लाख की कुल आबादी वाले मंगोलिया में 10 दिनों के भीतर करीब एक लाख श्रद्धालुओं ने मठ पहुंचकर पवित्र अवशेषों के दर्शन किए।

असम : कुमार भास्कर वर्मा सेतु पर आयोजित प्रगति पथ यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल

गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु पर गुरुवार को 'प्रगति पथ यात्रा' आयोजित की गयी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, स्थानीय विधायक विजय गुप्ता एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ज्ञात हो कि विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया। जिसमें केंद्रीय मंत्री के साथ ही समाज के सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के आरंभ में कुमार भास्कर वर्मा सेतु पर आयोजित 'प्रगति पथ यात्रा' के साथ हुई। यात्रा के दौरान उपस्थित जनसमुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे में आए क्रांतिकारी बदलावों और जनकल्याणकारी उपलब्धियों को विस्तार से साझा किया गया। इसके पश्चात, उत्तर गुवाहाटी स्थित ऐतिहासिक श्री दोल गोविन्द मंदिर परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर्यावरण संरक्षण और हरित चेतना का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' में स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्ध जनों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया गया, जहां देश और राज्य के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसी कड़ी में, एक विशेष जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से स्थानीय नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उनके बहुमूल्य विचार, प्रतिक्रियाएं और सुझाव प्राप्त किए गए। असम की निरंतर होती प्रगति, सुदृढ़ और आधुनिक होती आधारभूत संरचना और हर वर्ग में दिख रहा जनभागीदारी का यह अभूतपूर्व उत्साह इस बात का प्रतीक है कि 'विकसित भारत' का संकल्प अब एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है, जो देश को एक नई और संप्रभु शक्ति प्रदान कर रहा है।

पर्यटन में बदलाव के 12 वर्ष: देश में पर्यटन स्थलों पर 24 घंटे हेल्पलाइन, टूरिस्ट पुलिस व्यवस्था

नई दिल्ली। भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। पर्यटन में बदलाव के 12 साल के तहत देश में एक ऐसा मजबूत पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा रहा है, जहां घरेलू और विदेशी यात्री बिना किसी डर के घूम-फिर सकें। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार सुरक्षित और स्वागत-पूर्ण यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 24 घंटे बहुभाषी हेल्पलाइन और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष टूरिस्ट पुलिस की तैनाती जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं जमीनी स्तर पर लागू की हैं। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति, शिकायत या तुरंत जानकारी के लिए सरकार ने एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1363 जारी किया है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे काम करती है। विदेशी और स्थानीय पर्यटकों की सुविधा के लिए यह सेवा 12 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि भाषा की वजह से किसी को मदद मिलने में कोई बाधा न आए। इसके अलावा, पर्यटकों को जमीनी स्तर पर तत्काल और विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में टूरिस्ट पुलिस की तैनाती की गई है। वर्तमान में यह व्यवस्था गोवा, केरल, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर सहित देश के 15 प्रमुख राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी तरह सक्रिय है। इस विशेष पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकना, पर्यटकों का मार्गदर्शन करना और उनके साथ होने वाले किसी भी दुर्व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई करना है। मंत्रालय के मुताबिक इस नई और आधुनिक व्यवस्था के जरिए केंद्र सरकार का लक्ष्य हर यात्री को यह भरोसा दिलाना है कि आपकी यात्रा आपको जहां भी ले जाए, मदद हमेशा आपके आस-पास ही होगी।

मणिपुर में उग्रवादी हमला, दो ग्रामीणों की मौत, कई घर जलाए

एजेंसी, कामजोंग

- मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने कामजोंग तथा आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी

मणिपुर के कमजोंग जिले में गुरुवार तड़के उग्रवादी हमले में दो ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग प्रभावित हुए। हमले के दौरान कम से कम छह घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे गांव में दहशत का माहौल फैल गया। जानकारी के अनुसार, भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों का एक समूह सुबह होते ही कमजोंग जिले के कुल्तुह कुकी गांव में घुस आया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद हमलावरों ने कई आवासीय मकानों में आग लगा दी। अचानक हुए इस हमले से भयभीत ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए आसपास के जंगलों की ओर भाग गए।

ईस्टर्न कुकी चीफ्स एसोसिएशन ने मृतकों की पहचान कुल्तुह चर्च के हेड डीकन लेटमिनलुन हाओकिप और चर्च यूथ चेयरमैन लुनमिनथांग हाओकिप के रूप में की है। घटना में दो अन्य ग्रामीणों के घायल होने की भी सूचना है।

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पड़ोसी जिले कांगपोकपी में अपहृत छह नागा समुदाय के लोगों के शव बरामद होने के बाद पूरे राज्य में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस घटना को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा सेनापति जिले में एक राजनीतिक दल के कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने कामजोंग तथा आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की प्रतिशोधात्मक सामुदायिक हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।

इस बीच, विभिन्न कुकी सामाजिक संगठनों ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सुनियोजित आतंकी कार्रवाई बताया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हमले में शामिल उग्रवादी संगठन की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

अनियमितताओं को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आज

एजेंसी, नई दिल्ली

देश में उपभोक्ता सामानों की कीमतों में पारदर्शिता की कमी को लेकर गैर-सरकारी संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (एबीजीपी) राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार (12 जून) को यहां के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगा। दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायणभाई शाह ने कहा कि संगठन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के सामने स्पष्ट एवं वैज्ञानिक मानदंड, युक्तिसंगत मूल्य, मुद्रण सीमा का निर्धारण और नियामक संस्था का गठन जैसी कई मांगे रखेगा।

शाह ने कहा कि वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुकी है। शुरुआत में सरकार ने इसे उपभोक्ताओं को स्थानीय करों की मनमानी से बचाने के लिए लागू किया था, लेकिन आज यह निर्माताओं और व्यापारियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है।

शाह ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि अगर सरकार तत्काल कदम नहीं उठाती है तो मुंबई में उचित समय पर एमआरपी के मुद्दे को लेकर एक बैठक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा संगठन राज्य सरकार के रुख, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की भूमिका को लेकर लगातार संपर्क में रहेगा और मांगें पूरी करने के लिए दबाव बनाए रखेगा। मुंबई के अलावा गुवाहाटी और देश के अन्य हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि आज भी एक बड़ी आबादी को एमआरपी के सही नियमों की जानकारी नहीं है। उनका मानना है कि सरकार के स्पष्ट नियमों के अभाव में कंपनियां खुद ही मनमाना मूल्य प्रिंट कर रही हैं। इसके कारण वास्तविक लागत मूल्य और छपे हुए मूल्य (एमआरपी) के बीच का संबंध खत्म हो चुका है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजिटल निगरानी के लिए एनएसवी प्रणाली लागू करने का फैसला

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी और रखरखाव व्यवस्था को डिजिटल एवं तकनीक आधारित बनाने के लिए नेटवर्क सर्वे वाहन (एनएसवी) प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार ये अत्याधुनिक नेटवर्क सर्वे वाहन 3डी लेजर तकनीक, जीपीएस और हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों से लैस हैं। ये सड़क की सतह पर मौजूद गड्ढों, दरारों और अन्य खामियों की पहचान कर विस्तृत डिजिटल डेटा तैयार करेंगे। पहले जहां एक दिन में 20 से 80 किलोमीटर सड़क का सर्वे किया जाता था, वहीं अब यह क्षमता बढ़कर लगभग 300 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है।

एनएसवी द्वारा एकत्र डेटा 48 घंटे के भीतर केंद्रीय सिस्टम तक पहुंचाया जाएगा और 10 दिनों के भीतर उसका विश्लेषण कर कार्रवाई योग्य रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पहले यह प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी होती थी। मंत्रालय ने कहा कि सभी रिपोर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंधित एजेंसियों को भेजी जाएंगी और मरम्मत कार्य की निगरानी भी सिस्टम आधारित होगी। नई व्यवस्था के तहत निरीक्षण अधिकारी मोबाइल ऐप के जरिए मौके पर ही एनएसवी रिपोर्ट देख सकेंगे, जियो-टैग्ड फोटो अपलोड कर सकेंगे और टिप्पणी भी कर पाएंगे। मंत्रालय के अनुसार इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता सुधारना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और रखरखाव प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

अमृतसर में 30 किलो हेरोइन बरामद, दो नाबालिग समेत छह नशा तस्कर पकड़े गए

एजेंसी, चंडीगढ़

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 30.045 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके सीमा पार संचालित नशा तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को चंडीगढ़ में अमृतसर की फतेह सिंह कॉलोनी निवासी गौतम (24), अमृतसर के छेहरटा निवासी कबीर उर्फ काकू (22), अमृतसर निवासी समीर उर्फ सभरवाल (18) तथा अमृतसर की ऑर्किड वैली निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ कीड़ा (18) को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि कबीर उर्फ काकू का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और उसके खिलाफ थाना छेहरटा में एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से मामला दर्ज है।

नशों की खेप बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल वे नशा तस्करी के लिए कर रहे थे। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरफ्तार नशा तस्कर दुबई में एक तस्कर के संपर्क में थे, जो सीमा पार से हेरोइन की तस्करी में उनकी सहायता कर रहा था। उन्होंने बताया कि उक्त तस्कर के निर्देशों पर निर्धारित स्थानों से नशे की खेप प्राप्त करके उसे पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में आगे सप्लाई किया जाता था।

डीजीपी ने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने तथा वित्तीय स्रोतों का पता लगाकर संभावित हवाला संबंधों का खुलासा करने के लिए आगे जांच जारी है।

पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जांच के अनुसार दुबई का तस्कर इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है, जो पहले से ही 42 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी मामले तथा 10 किलोग्राम आईसीई बरामदगी मामले सहित तीन बड़े एनडीपीएस मामलों में पुलिस को वांछित है। उन्होंने बताया कि दुबई में बैठकर संचालित करने वाला यह तस्कर नाबालिगों सहित युवाओं को धन का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर उन्हें नशे की खेप प्राप्त करने तथा आगे सप्लाई करने जैसे कार्यों में इस्तेमाल करता था।

ट्विशा शर्मा मौत मामला: दिल्ली एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच में आई तेजी

एजेंसी, भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम को दिल्ली एम्स द्वारा तैयार की गई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंप दी गई है। इसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। ट्विशा शर्मा के अधिवक्ता अंकुर पांडेय ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच एजेंसी को मिल गई है। फिलहाल सीबीआई की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर रही है और इसे जल्द ही उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अदालत के निर्देशों के आधार पर ही जांच की आगामी दिशा तय होगी।

सूत्रों के अनुसार, अब सीबीआई का मुख्य फोकस गर्भधारण, गर्भपात और उसके बाद हुई मौत के बीच की परिस्थितियों को समझने पर है। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गर्भपात और मौत के बीच घटनाक्रम किस प्रकार विकसित हुआ। इसके लिए पारिवारिक परिस्थितियों, फोन रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और अन्य तथ्यों का भी विश्लेषण पूरा हो चुका है। दोनों पक्षों के दावों में अंतर होने के कारण जांच की हर कड़ी को बारीकी से परखा जा रहा है।

हालांकि, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर सीबीआई ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। रिपोर्ट में शरीर पर मिले चोट के निशानों तथा गर्भपात से जुड़े तथ्यों का भी परीक्षण किया जा रहा है। इधर, क्राइम सीन री-क्रिएशन के दौरान केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के विशेषज्ञों द्वारा जुटाए गए तकनीकी साक्ष्यों और डमी टेस्ट की अंतिम रिपोर्ट का मूल्यांकन भी तेज कर दिया गया है। एम्स की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मिलान डमी टेस्ट के निष्कर्षों से किया जा रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला आत्महत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने अथवा किसी साजिश से जुड़ा है।

मामले में शुरुआती जांच से जुड़ी लापरवाहियां भी सामने आ चुकी हैं। जांच अधिकारी एवं कटारा हिल्स थाने के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा पर घटना में इस्तेमाल किए गए लिगेचर बेल्ट को चिकित्सकों की टीम तक पहुंचाने में दो दिन की देरी का आरोप है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इन दोनों पहलुओं को गंभीर चूक माना गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद एसआई दिनेश शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।

सीबीआई अधिकारियों का मानना है कि मेडिकल, फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों के पूर्ण विश्लेषण के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। एजेंसी फांसी के फंदे से जुड़े तथ्यों की भी बारीकी से जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई की एक विशेष टीम ट्विशा शर्मा के मोबाइल फोन और लैपटॉप की डिजिटल जांच में जुटी हुई है। डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे चैट, कॉल रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से घटनाक्रम की अहम कड़ियां सामने आ सकें।

मप्र से राज्यसभा की तीनों सीटें भाजपा ने जीती, तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

एजेंसी, भोपाल

मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जीत ली है। पार्टी के तीनों उम्मीदवारों तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को गुरुवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। राज्यसभा निर्वाचन के तय कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारी से नाम वापसी का गुरुवार को अंतिम दिन था। दोपहर 3 बजे नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद भाजपा के तीन उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया, जिनमें तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट शामिल हैं। रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने भाजपा के तीनों निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों को निर्वाचन के प्रमाण पत्र सौंप दिए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। इनमें दो सीटें भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते की है। इन तीनों रिक्त होने वाली सीटों पर द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए भाजपा के तीन उम्मीदवार-तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल तथा कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन भाजपा की आपत्ति के बाद हलफनामे में अनियमितताएं पाए जाने के आधार पर कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गत मंगलवार को खारिज कर दिया गया था। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद शेष तीन नामांकन पत्रों की बुधवार को संवीक्षा (स्क्रूटनी) हुई थी। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा द्वारा बुधवार को ही उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीनों उम्मीदवारों तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट के नाम शामिल थे।

सीबीआई ने गणेश बालासो काले को थाईलैंड से किया प्रत्यर्पित

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को साइबर धोखाधड़ी के मामले में वांछित भगोड़े गणेश बालासो काले को थाईलैंड से प्रत्यर्पण कराने में गुरुवार को कामयाबी मिली है। उसे 24 मई को बैंकॉक में थाई अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 जून को भारत भेजा गया। सीबीसीआई के अधिकारी आरोपित को लेकर आज मुंबई पहुंच गए।

सीबीआई ने बताया कि मुंबई पहुंचने के बाद गणेश बालासो काले को महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने अपनी हिरासत में ले लिया। काले पर आरोप है कि उसने ऑनलाइन पार्ट-टाइम नौकरी का लालच देकर लोगों से निवेश के नाम पर धन जमा कराया और बाद में उन्हें धोखा दिया। वह एक नेटवर्क चलाता था जिसमें निर्दोष व्यक्तियों को शामिल कर उनके बैंक खातों का उपयोग अवैध धन हस्तांतरण के लिए किया जाता था।

इसके अलावा उसने सह-आरोपितों को मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए थे। सीबीआई ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सीबीआई ने बताया कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से आरोपित को मात्र 20 दिनों के भीतर रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद खोजकर भारत लाया गया।

मप्र सब्जी उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा, चार वर्षों में हुई 21.58 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि

एजेंसी, भोपाल

मध्य प्रदेश ने सब्जी उत्पादन में एक नई उपलब्धि हासिल की है। विगत चार वर्ष में प्रदेश के सब्जी उत्पादन में लगभग 21.58 लाख मीट्रिक टन की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश इस समय देश में सब्जियों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ष 2026 को "किसान कल्याण वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, कृषि का विविधीकरण तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। जनसम्पर्क अधिकारी अनिल वशिष्ठ ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने बताया कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा "समृद्ध किसान-समृद्ध मध्य प्रदेश" की थीम पर सब्जी क्षेत्र विस्तार की व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रदेश की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, सिंचाई संसाधनों का विस्तार तथा किसानों द्वारा आधुनिक तकनीकों को अपनाने के कारण सब्जी उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन 236.41 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 257.99 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। यह वृद्धि राज्य के कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र की सुदृढ़ प्रगति को दर्शाती है।

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर सब्जियों का कुल उत्पादन लगभग 2177 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी लगभग 259 लाख मीट्रिक टन है। देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रदेश के लाखों किसान सब्जी उत्पादन से अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं और देश की बढ़ती मांग को भी पूरा कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों द्वारा प्याज, आलू, टमाटर, बैंगन, फूल-गोभी, पत्ता-गोभी, हरी मटर, भिंडी, पालक, लौकी, अरबी, करेला, ककड़ी, मूली, तुरई (तोरी), गाजर, शकरकंद, शिमला मिर्च, परवल सहित अनेक प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इनमें प्याज उत्पादन का विशेष स्थान है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र प्याज की खेती के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष 2022-23 में प्याज का रकबा 2.17 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर लगभग 2.30 लाख हैक्टेयर हो गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में छोटी जोत वाले किसानों को सब्जी फसलों के उत्पादन के लिये ओर प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। जिनसे कम भूमि में अधिक आय प्राप्त हो सके। सब्जी उत्पादन इस दृष्टि से सबसे प्रभावी विकल्पों में से एक होने से ही किसान कल्याण वर्ष में सब्जी क्षेत्र विस्तार को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

फिर सुलग़ रही खाड़ीः होर्मुज जलडमरूमध्य बंद,दुनियाँ में हड़कंप-भारत की ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई और अर्थव्यवस्था पर मंडराता संकट? -व्यापक समग्र विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» ईरान नें होर्मुज जलडमरूमध्य बंद से ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं

» होर्मुज जलडमरूमध्य बंद से केवल क्षेत्रीय नहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका की संभावना?, इस जलमार्ग में व्यवधान का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर दिखाई देता है -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल का केंद्र बन गया है। 11 जून 2026 को स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दुनियाँ के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य, को सभी वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद करने की घोषणा कर दी। ईरानी सैन्य नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। यह कदम कथित रूप से अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री टकराव तथा अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के बाद उठाया गया है। इसके साथ ही वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारी बेचैनी फैल गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 95.40 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई लगभग 92.6 डॉलर प्रतिबैरल तक पहुंच गया है। दुनियाँ की लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है, इसलिए इस घटनाक्रम ने ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने भी खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताव्यक्त की है। वर्तमान घटनाक्रम केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह बिल्कुल सही है क्रि होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा व्यवस्था की धुरी माना जाता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री मार्ग सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, इराक और ईरान जैसे प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशों के निर्यात का मुख्य रास्ता है। सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन करोड़ों बैरल तेल और विशाल मात्रा में एलएनजी इसी मार्ग से दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचती है। यही कारण है कि जब भी इस जलमार्ग में व्यवधान आता है, उसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर दिखाई देता है। वर्तमान संकट में भी निवेशकों और ऊर्जा कंपनियों ने आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए तेल खरीदना शुरू कर दिया,जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल उछाल देखने को मिला। साथियों, अंतरराष्ट्रीय बाजारों की पहली प्रतिक्रिया तेल कीमतों में तेजी के रूप में सामने आई है। ब्रेंट क्रूड लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया है जबकि डब्ल्यूटीआई भी 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि यदि जलडमरूमध्य लंबे समय तक बंद रहता है या सैन्य संघर्ष और बढ़ता है तो तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर भी जा सकती हैं। वैश्विक वित्तीय बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ने की आशंका है क्योंकि ऊर्जा लागत लगभग हर आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करती है। साथियों, भारत के लिए यह संकट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी आवश्यकता का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से पूरा होता है और उसका एक बड़ा भाग होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है। इसलिए इस मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट का सीधा असर भारतीय ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। यदि तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा,चालू खाता घाटा बढ़ सकता है और रुपये पर दबाव पड़ सकता है। ऊर्जा आयात पर बढ़ती लागत अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचती है और महंगाई को बढ़ावा देती है।सबसे पहला प्रभाव पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने से भारतीय तेल विपणन कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। यदि मौजूदा तनाव कुछ और दिनों या सप्ताहों तक बना रहता है तो पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का अनुमान है कि लंबी अवधि तक ऊंचे तेल मूल्य बने रहने पर ईंधन की कीमतों में कई रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर आम नागरिकों, किसानों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र पर पड़ेगा।पेट्रोल और डीजल केवल वाहन चलाने का साधन नहीं हैं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं। डीजल की कीमत बढ़ने का अर्थ है कि ट्रकों, बसों और मालवाहक वाहनों की परिचालन लागत बढ़ जाएगी। जब परिवहन महंगा होता है तो फल, सब्जियां, दूध, अनाज, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि तेल कीमतों में वृद्धि को अक्सर 'महंगाई की जननी' कहा जाता है। एक बार यदि ईंधन लागत बढ़ती है तो उसका असर अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में सटीकता से दिखाई देता है। साथियों, 7 जून 2026 से मृग लग गया है व खेती के कार्य शुरू हो चुके हैं,कृषि क्षेत्र भी इस संकट से अछूता नहीं रहेगा। भारत में सिंचाई, कृषि मशीनरी और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का बड़ा हिस्सा डीजल पर निर्भर है। डीजल महंगा होने से किसानों की लागत बढ़ेगी और इसका असर खाद्यान्न कीमतों पर पड़ सकता है। इसके अलावा उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर निर्भर है। यदि ऊर्जा लागत बढ़ती है तो उर्वरकों का उत्पादन भी महंगा हो सकता है।विमानन क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ सकता है। विमान ईंधन की लागत एयरलाइंस के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा होती है। यदि अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई किराए में वृद्धि संभव है। इससे पर्यटन उद्योग, व्यापारिक यात्राओं और विमानन क्षेत्र की मांग पर असर पड़ सकता है। साथियों, भारत के लिए चिंता का एक और बड़ा विषय एलएनजी यानी तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति है। भारत कतर सहित खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में एलएनजी आयात करता है और उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। यदि इस मार्ग में लंबे समय तक व्यवधान रहता है तो सीएनजी और पीएनजी की उपलब्धता तथा कीमतों पर असर पड़ सकता है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ- साथ बिजली उत्पादन, उर्वरक निर्माण और औद्योगिक इकाइयों की लागत भी बढ़ सकती है।हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन भारत पूरी तरह असहाय नहीं है। पिछले वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मौजूद हैं जिनका उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों में किया जा सकता है।विशाखापट्टनम मैंगलोर और पादुर जैसेस्थानों पर स्थापित भूमिगत भंडारण सुविधाएं सीमित अवधि के लिए देश को राहत प्रदान कर सकती हैं। ये भंडार किसी भी अचानक आपूर्ति संकट के दौरान महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच साबित हो सकते हैं।इसके अतिरिक्त भारत नेऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति अपनाई है। रूस से बढ़ते तेल आयात ने भारत को एक वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत उपलब्ध कराया है। रूस से आने वाला तेल सामान्यतः अन्य समुद्री मार्गों से आता है, इसलिए होर्मुज संकट की स्थिति में यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। यदि आवश्यकता हुई तो भारत रूस तथा अन्य गैर-खाड़ी आपूर्ति कर्ताओं से आयात बढ़ाने की दिशा में सटिका से कदम उठा सकता है। साथियों, सऊदी अरब,यूएई और अन्य खाड़ी देशों के पास भी कुछ वैकल्पिक पाइपलाइन मार्ग उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से सीमित मात्रा में तेल निर्यात किया जा सकता है। हालांकि ये मार्ग होर्मुज के पूर्ण विकल्प नहीं हैं, फिर भी वे वैश्विक बाजार में आपूर्ति के पूर्ण ठहराव को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसी कारण ऊर्जा बाजारों में अभी भी आशा बनी हुई है कि राजनयिक प्रयासों के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा।भू-राजनीतिक दृष्टि से यह संकट केवल तेल या गैस तक सीमित नहीं है। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व समुद्री व्यापार के सबसे संवेदनशील मार्गों में से एक है। इसके बंद होने से बीमा लागत, माल ढुलाई शुल्क और शिपिंग समय में वृद्धि होती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़ते हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कोविड-19 महामारी और यूक्रेन संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही आपूर्ति व्यवधानों का अनुभव कर चुकी है; ऐसे में होर्मुज संकट नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। साथियों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते हमले और समुद्री असुरक्षा वैश्विक व्यापार तथा भारतीय नागरिकों दोनों के लिए चिंता का विषय हैं। भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों, व्यापारिक जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए नई दिल्ली स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक समाधान का समर्थन कर रही है।वर्तमान परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह संकट कितने समय तक चलता है। यदि राजनयिक प्रयास सफल होते हैं और जलडमरूमध्य जल्द खुल जाता है तो तेल बाजारों में स्थिरता लौट सकती है। लेकिन यदि सैन्य टकराव बढ़ता है या मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लग सकता है। तेल की कीमतें तीन अंकों तक पहुंच सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और कई आयात- निर्भर देशों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना केवल पश्चिम एशिया का संकट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, महंगाई, समुद्री सुरक्षा और भू-राजनीतिक स्थिरता,सभी इस एक समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं। भारत के लिए यह समय ऊर्जा स्रोतों में विविधता, रणनीतिक भंडारों के विस्तार और दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयासों को और तेज करने का है।आने वाले दिनों में दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी रहेंगी, क्योंकि होर्मुज की स्थिति केवल तेल की कीमतों का नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता का भी निर्धारण करेगी।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

कब थमेगी नन्हे हाथों से मजदूरी?

लेखक- दिलीप कुमार पाठक

यह हमारे समाज का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम रोज देखते हैं और देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं। एक तरफ वे बच्चे हैं जो सुबह-सुबह अच्छे कपड़े पहनकर, भारी-भारी बैग टांगे स्कूल जाते दिखते हैं। उनकी आंखों में ढेर सारे सपने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ, ठीक उसी सड़क के पार किसी दुकान या ढाबे पर कोई छोटा सा बच्चा जूठे बर्तन साफ कर रहा होता है। उसके हाथ काम करते-करते थक चुके होते हैं और उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही डर होता है कि कहीं मालिक डांट न दे। यह कहानी किसी एक शहर की नहीं है, हमारे आस-पास हर जगह यही हाल है। हर साल 12 जून को हम बाल श्रम निषेध दिवस मनाकर सोच लेते हैं कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन सच तो यह है कि एक दिन तय कर देने से इन बच्चों की जिंदगी नहीं बदलती। बचपन का मतलब क्या होता है? बचपन यानी बिना किसी टेंशन के जीना, दोस्तों के साथ खेलना, मिट्टी में खेलना और बस मजे करना। लेकिन जब इन्हीं नन्हे हाथों में खिलौनों या किताबों की जगह भारी ईंटें, चाय के कप या साफ-सफाई का झाड़ू थमा दिया जाता है, तो सिर्फ एक बच्चा मजदूरी नहीं कर रहा होता बल्कि उस बच्चे का पूरा भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गरीबी और लाचारी इन बच्चों से हंसने-खेलने के दिन छीन लेती है। कारखानों के गंदे धुएं में, छोटे होटलों के बर्तनों के बीच और खेतों की तेज धूप में इनका बचपन इस तरह पिस जाता है कि ये बच्चे ढंग से मुस्कुराना तक भूल जाते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इन बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम पर क्यों लगना पड़ता है? इसका सबसे सीधा जवाब है - घर की गरीबी और लाचारी। जब किसी परिवार में दो वक्त के खाने का ठिकाना न हो, तो मजबूर होकर मां-बाप अपने ही बच्चे को थोड़े से पैसों के लिए काम पर भेज देते हैं। लेकिन इस लाचारी का सबसे गंदा फायदा हमारा पढ़ा-लिखा समाज उठाता है। छोटे दुकानदार, ठेकेदार और यहाँ तक कि बड़े घरों के लोग भी बच्चों को काम पर रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत कम पैसों में बिना कोई नखरा किए दिन-रात काम करते हैं, और वे अपने हक के लिए कभी लड़ भी नहीं सकते। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसा हुआ बच्चा कभी पढ़-लिख नहीं पाता और बड़ा होकर भी इसी गरीबी में फंसा रह जाता है। कहने को तो हमारे देश में बाल मजदूरी के खिलाफ बहुत कड़े कानून बने हुए हैं। कानून कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना जुर्म है और हर बच्चे को स्कूल जाने का पूरा हक है। लेकिन सच यह है कि सिर्फ कागजों पर नियम बना देने से किसी गरीब का पेट नहीं भरता। जब तक जमीनी स्तर पर जाकर इन नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हर नुक्कड़ और चौराहे पर हमें कोई न कोई बच्चा गाड़ियां साफ करता हुआ या चाय की केतली थामे हुए ही दिखेगा। हम हमेशा सरकार और सिस्टम को कोसकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन समाज को बदलने की शुरुआत हमारे अपने घर और हमारी सोच से होती है। अगली बार जब आप किसी दुकान या होटल पर किसी बच्चे को काम करते देखें, तो वहां से चुपचाप चाय पीकर निकलने के बजाय दुकानदार से टोककर सवाल करें। अपने खुद के घरों में छोटे बच्चों से काम करवाना बिल्कुल बंद करें। अगर हम थोड़े भी सक्षम हैं, तो किसी एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। बाल मजदूरी को रोकना सिर्फ कोई कानूनी नियम नहीं है, बल्कि यह हमारी इंसानियत का तकाजा है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक उसकी आने वाली पीढ़ी अनपढ़ रहे। आइए, इस बाल श्रम निषेध दिवस पर सिर्फ बड़े-बड़े भाषण न दें, बल्कि अपने दिल से एक वादा करें। अपने आस-पास किसी भी बच्चे का बचपन चोरी होने से बचाएं।

विकसित भारत का मार्ग : नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक से निकला नया विकास मंत्र

आलेख – विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला'

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं थी,बल्कि भारत के भविष्य की विकास दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विमर्श था। "विकसित राज्य से विकसित भारत" की थीम पर आयोजित इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने प्रदेशों की आवश्यकताओं, चुनौतियों और विकास संबंधी सुझावों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा।सर्वविदित रहे यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच चुकी है और अगले दशक में इसे 10 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।ऐसे में राज्यों की भागीदारी और उनकी विकास क्षमता निर्णायक महत्व रखती है।बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि विकसित भारत का सपना दिल्ली में बैठकर पूरा नहीं किया जा सकता।इसके लिए राज्यों को विकास का इंजन बनना होगा। उन्होंने राज्यों से निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन,कृषि आधुनिकीकरण,कौशल विकास और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने का आह्वान किया।इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा रखे गए सुझाव और मांगें रहीं।इन सुझावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्यों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हो सकती हैं,लेकिन लक्ष्य एक ही है—तेज,समावेशी और सतत विकास। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को कृषि एवं औद्योगिक हब बनाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं,लॉजिस्टिक कॉरिडोर और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार पर बल दिया। उन्होंने केंद्र से अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहयोग की माँग की।नबाब सिंह सैनी ने हरियाणा को विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए औद्योगिक गलियारों, कौशल विकास और एमएसएमई क्षेत्र को और मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई।उन्होंने कृषि में ड्रोन तकनीक तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने का सुझाव भी दिया।भजन लाल शर्मा ने जल संकट को राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए नदी जोड़ो परियोजनाओं और जल संरक्षण कार्यक्रमों में केंद्र के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।साथ ही उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका को और मजबूत करने की बात कही।योगी आदिनाथ ने उत्तर प्रदेश के तेजी से बढ़ते औद्योगिक निवेश,एक्सप्रेसवे नेटवर्क और डिफेंस कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए राज्यों को अधिक वित्तीय लचीलापन देने की मांग रखी ताकि विकास परियोजनाओं को गति मिल सके।देवन्द्र फ्रडनवीस ने मुंबई महानगर क्षेत्र, सेमीकंडक्टर उद्योग और हरित ऊर्जा निवेश को राष्ट्रीय विकास का प्रमुख आधार बताते हुए वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों को अधिक नीति समर्थन देने की बात कही।पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने सड़क,रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बताया।उनका मत था कि बेहतर संपर्क व्यवस्था ही क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय एकीकरण का आधार बनेगी।इस बैठक में कृषि क्षेत्र पर विशेष चर्चा हुई।आज भी लगभग 45 प्रतिशत भारतीय आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। राज्यों ने प्राकृतिक खेती,सूक्ष्म सिंचाई,कृषि निर्यात और भंडारण सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। कई मुख्यमंत्रियों ने कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता बताई। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र भी चर्चा के केंद्र में रहे। राज्यों ने चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने, जिला अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने तथा नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पर बल दिया।भारत की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इसलिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने पर व्यापक सहमति दिखाई दी। हरित ऊर्जा को लेकर भी महत्वपूर्ण विचार सामने आए। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है।राजस्थान,गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों का भी उल्लेख हुआ।आज भारत में 150 करोड़ से अधिक आधार प्रमाणीकरण प्रतिमाह हो रहे हैं और यूपीआई लेन-देन विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क बन चुका है।राज्यों ने डिजिटल प्रशासन और सेवा वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों को अपनाने का सुझाव दिया।इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सहकारी संघवाद की भावना का और अधिक मजबूत होना रहा।केंद्र और राज्यों के बीच संवाद,सहयोग और साझेदारी के माध्यम से विकास के नए मॉडल विकसित करने पर सहमति बनी। यह स्पष्ट हुआ कि विकसित भारत का मार्ग राज्यों से होकर ही गुजरता है।

निष्कर्षतः नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक ने केवल नीतिगत चर्चा नहीं की,बल्कि भारत के अगले दो दशकों के विकास का व्यापक खाका प्रस्तुत किया।मुख्य मंत्रियों के सुझावों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विकास दृष्टि ने यह संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत का विकास मॉडल अधिक विकेंद्रीकृत,सहभागी और परिणामोन्मुख होगा।यदि इस बैठक में सामने आए सुझावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल एक सरकारी संकल्प नहीं,बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक उपलब्धि बन सकता है।यही इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है।

बचपन को श्रम नहीं, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिलें

लेखक- ललित गर्ग

हर वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानवता के अंतःकरण को झकझोरने वाला अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं होता। उसके हाथों में औजार, ईंट, बर्तन, हथौड़े, कूड़े की बोरी या कारखानों की मशीनें नहीं, बल्कि किताबें, खिलौने, रंग, सुनहले सपने और संभावनाएं होनी चाहिए। बचपन जीवन का वह स्वर्णिम काल है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, संस्कार, शिक्षा और भविष्य की नींव रखी जाती है। यदि यही काल श्रम, शोषण और अभाव की भट्टी में झोंक दिया जाए तो केवल एक बच्चे का नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन-आईअलओ द्वारा 2002 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की भयावहता के प्रति वैश्विक चेतना जगाना और इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को गति देना है। वर्ष 2026 में भी यह दिवस ऐसे समय पर आ रहा है जब दुनिया तकनीकी विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक प्रगति के नए आयाम छू रही है, लेकिन दूसरी ओर करोड़ों बच्चे आज भी शिक्षा और बचपन के अधिकार से वंचित हैं। यह विडम्बना मानव सभ्यता के सामने एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। जब हम किसी ढाबे, होटल, चाय की दुकान, कारखाने, गैरेज, ईंट-भट्टे, खेत या ट्रैफिक सिग्नल पर किसी मासूम बच्चे को कठिन श्रम करते देखते हैं, तब अक्सर हमारी संवेदना कुछ क्षणों के लिए जागती है और फिर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कब तक हम इस पीड़ा को सामान्य मानते रहेंगे? क्या हम उस बचपन की चीख नहीं सुन पा रहे जो अपने अधिकारों से वंचित होकर मजदूरी के अंधेरे में खो रहा है? आज भी विश्व में करोड़ों बच्चे किसी न किसी रूप में बाल श्रम में संलग्न हैं। इनमें से बड़ी संख्या खतरनाक परिस्थितियों में काम करती है, जहां उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास बाधित होता है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, विस्थापन, तस्करी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और कमजोर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं बाल श्रम की प्रमुख वजहें हैं। परिवार की आर्थिक विवशताएं बच्चों को स्कूल की बजाय काम की दुनिया में धकेल देती हैं। लेकिन गरीबी का समाधान बच्चों से काम कराना नहीं, बल्कि परिवारों को सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं है; यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, आत्मविश्वास और भविष्य छीन लेता है। जो बच्चा विद्यालय में होना चाहिए, वह यदि कारखाने में है, तो यह केवल उस बच्चे की नहीं, पूरे समाज की विफलता है। बाल श्रम गरीबी का चक्र भी बनाए रखता है, क्योंकि अशिक्षित बच्चा बड़ा होकर कम आय वाले कार्यों तक सीमित रह जाता है और अगली पीढ़ी भी उसी अभाव में जीने को मजबूर होती है। भारत सहित अनेक देशों में बाल श्रम रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईअलओ के कन्वेंशन 138 और कन्वेंशन 182 न्यूनतम कार्य आयु और बाल श्रम के सबसे खतरनाक रूपों पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। भारत में भी बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार कानून मौजूद हैं। लेकिन कानूनों की प्रभावशीलता उनके कठोर और ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कई बार कानूनी प्रावधान होने के बावजूद बाल श्रम छिपे हुए रूपों में जारी रहता है। आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने की है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जन-जागरण अभियान चलाए जाने चाहिए। विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, मीडिया, उद्योग जगत और नागरिक समाज को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और महिला अधिकारों को लेकर वैश्विक चेतना विकसित हुई है, उसी प्रकार बाल अधिकारों के लिए भी विश्वव्यापी जनमत तैयार करना होगा। कैसा विरोधाभास है कि हमारा समाज, सरकार और राजनीतिज्ञ बच्चों को देश का भविष्य मानते नहीं थकते लेकिन क्या इस उम्र के लगभग 25 से 30 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी के जरिए उनका बचपन और उनसे पढने का अधिकार छीनने का यह सुनियोजित षड्यंत्र नहीं लगता? मिसाल के तौर पर एक कानून बनाकर हमने बच्चों से उनका बचपन छिनने की कुचेष्टा की है। इस कानून में हमने यदि पारिवारिक कामधंधा या रोजगार है तो 4 से 14 की उम्र के बच्चों से कानूनन काम कराया जा सकता है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कैसी विडम्बना है कि जब इस उम्र के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, खानदानी व्यवसाय के नाम पर एक पूरी पीढ़ी को शिक्षा, खेलकूद और सामान्य बाल्य सुलभ व्यवहार से वंचित किया जा रहा है और हम अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर हकीकत में हम उन्हें पैसा कमाकर लाने की मशीन बनाकर अंधकार में धकेल रहे हैं।

विशेष रूप से डिजिटल युग में तकनीक का उपयोग बाल श्रम उन्मूलन के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शी निगरानी, बाल श्रम शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, त्वरित कार्रवाई तंत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियां विकसित की जा सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला में कहीं भी बाल श्रम का उपयोग न हो। जो कंपनियां ऐसा करती पाई जाएं, उनके विरुद्ध कठोर आर्थिक और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाल श्रम समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा है। केवल विद्यालय खोल देना पर्याप्त नहीं है; शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आकर्षित करे, जीवनोपयोगी कौशल दे और उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास करे। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार आवश्यक है। यदि परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी तो बच्चों को मजदूरी के लिए भेजने की मजबूरी भी कम होगी। हमें यह भी समझना होगा कि बचपन केवल जीवित रहने का नाम नहीं है; बचपन का अर्थ है सपने देखने की स्वतंत्रता, खेलने का अधिकार, सीखने का अवसर, स्नेहपूर्ण वातावरण और सुरक्षित भविष्य। जिस समाज में बच्चे मुस्कुरा नहीं सकते, वह समाज कभी वास्तविक विकास नहीं कर सकता। आर्थिक विकास की ऊंची इमारतें तब तक अधूरी हैं जब तक उनके नीचे किसी बच्चे का कुचला हुआ बचपन पड़ा हो। महान शिक्षाविद् नेल्सन मंडेला ने कहा था, "किसी समाज की आत्मा को जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है।" यदि हम सचमुच विकसित और संवेदनशील समाज बनना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों के प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। उन्हें दया का नहीं, अधिकार का विषय मानना होगा।

महिला टी20 विश्व कप

इन गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। महिला टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 12 जून से हो रही है। इंग्लैंड में आयोजित हो रहा यह इवेंट टी20 विश्व कप का 10वां संस्करण है। आइए देखते हैं कि पिछले 9 संस्करणों में किन दस गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं।

- महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगान स्कट के नाम है।
- मेगान ने 2016 से 2024 के बीच खेले 29 मैचों में 48 विकेट लिए हैं।
- दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल दूसरे नंबर पर हैं। इस्माइल ने 2009 से 2023 के बीच 32 मैचों में 43 विकेट लिए हैं।
- इंग्लैंड की ए श्रूबसोले तीसरी सफल गेंदबाज हैं। 2010 से 2020 के बीच 27 मैचों में उन्होंने 41 विकेट लिए।
- चौथे नंबर पर सर्वाधिक टी20 विश्व कप मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी हैं।
- पेरी ने 2009 से 2024 के बीच 47 मैचों में 40 विकेट लिए हैं।
- वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर ने 2009 से 2024 के बीच 35 मैचों में 33 विकेट लिए हैं, वे पांचवीं सफल गेंदबाज हैं।
- छठे नंबर पर न्यूजीलैंड की एमिलिया केर हैं। 2018 से 2024 के बीच 18 मैचों में केर ने 32 विकेट लिए हैं।
- दक्षिण अफ्रीका की मारिजेन कैप और वेस्टइंडीज की डियांड्रा डॉटिन संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर हैं।
- कैप ने 2009 से 2024 के बीच 32 मैचों में 31 और डॉटिन ने 2009 से 2024 के बीच 35 मैचों में 31 विकेट लिए हैं।
- इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टन, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर हैं।
- एक्लेस्टन ने 2018 से 2024 के बीच 18 मैच में 29 और डिवाइन ने 2009 से 2024 के बीच 38 मैच में 29 विकेट लिए हैं।
- भारत की पूनम यादव, वेस्टइंडीज की ए फ्लेचर और पाकिस्तान की निदा डार संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर हैं। पूनम ने 2014 से 2020 के बीच 18 मैचों में 28, फ्लेचर ने 2016 से 2024 के बीच 23 मैचों में 28 और डार ने 2010 से 2024 के बीच 33 मैचों में 28 विकेट लिए हैं।
- इंग्लैंड की नट सेवियर ब्रंट और ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर संयुक्त रूप से दसवें स्थान पर हैं। ब्रंट ने 2014 से 2024 के बीच 29 मैचों में 26 औरर गार्डनर ने 2018 से 2024 के बीच 23 मैचों में 26 विकेट लिए हैं।

श्रीलंका दौरे पर 9 साल बाद जाएगी टीम इंडिया

WTC 2025-27 का हिस्सा होंगे टेस्ट मैच

नई दिल्ली। भारतीय टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था और पारी व 300 रन से बेहतरीन जीत दर्ज की थी। मगर यह टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा नहीं था। अब टीम इंडिया 15 अगस्त 2026 से एक बार फिर अपना ङ्खञ्जष्ट 2025-27 का अभियान शुरू करेगी। इस संस्करण में यहां से भारत के लिए हर मुकाबले में जीत दर्ज करना लगभग जरूरी है। भारतीय टीम अगस्त में श्रीलंका का दौरा करेगी। इस दौरे के लिए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के शेड्यूल की जानकारी क्रिकबज ने शेयर की है। इस दौरे पर टीम इंडिया दो टेस्ट मैच खेलेगी। 9 साल बाद भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा करेगी। आखिरी बार 2017 में टीम इंडिया ने विराट कोहली की कप्तानी में श्रीलंका का दौरा किया था और 3-0 से टेस्ट सीरीज जीती थी। अब 9 साल बाद भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में श्रीलंका का दौरा करेगी।

श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का शेड्यूल

पहला टेस्ट : 15-19 अगस्त 2026, गॉल
दूसरा टेस्ट : 23-27 अगस्त 2026, कोलंबो (SSC)

WTC अंकतालिका में भारत -श्रीलंका का हाल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मौजूदा हाल की बात करें तो श्रीलंका टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है। श्रीलंकाई टीम ने अभी तक 2 मैच खेले हैं जिसमें से एक में उसे जीत मिली है और एक मैच ड्रॉ हुआ है। श्रीलंका का विनिंग पर्सेंटाइल 66.67 प्रतिशत है। जबकि भारतीय टीम अंकतालिका में बांग्लादेश से भी नीचे छठे स्थान पर है। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली सीरीज में घर पर बुरी तरह हाल झेलनी पड़ी थी। भारतीय टीम ने मौजूदा संस्करण में 9 मैच खेले हैं जिसमें से 4-4 मैच टीम ने जीते और हारे हैं। एक मैच ड्रॉ हुआ है। भारत का विनिंग पर्सेंटाइल 48.15 प्रतिशत है। भारतीय टीम को यहां से अगर फाइनल में जगह बनानी है तो श्रीलंका, न्यूजीलैंड दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज (बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी) में जीत दर्ज करनी होगी।

भारत के लिए शानदार टेस्ट डेब्यू

7 विकेट लेकर बने प्लेयर ऑफ द मैच; अब मानव सुतार को इंग्लैंड की काउंटी टीम ने किया साइन

नई दिल्ली। भारतीय टीम के लिए हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट डेब्यू के बाद मानव सुतार को इंग्लैंड के एक काउंटी क्लब ने साइन किया है। इंग्लिश काउंटी क्लब वार्विकशायर ने भारतीय खिलाड़ी को मौजूदा काउंटी चैंपियनशिप के सीजन के अगले दो राउंड के लिए साइन किया है। इसकी घोषणा क्लब के द्वारा बुधवार को की गई। मानव ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में कुल सात विकेट दोनों पारियों में झटके थे और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। वार्विकशायर ने उन्हें साइन करने के बाद आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, 'वार्विकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब मानव सुतार को शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद काफी उत्साहित है। भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूदा काउंटी चैंपियनशिप के अगले दो राउंड में सेलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे।' मानव सुतार 12 जून को वार्विकशायर और यॉर्कशायर के बीच होने वाले मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद अगले हफ्ते समरसेट के खिलाफ मैच के लिए भी वह मौजूद रहेंगे। क्लब के परफॉर्मेंस डायरेक्टर जेम्स थॉमस ने भी मानव का टीम में स्वागत किया। वहीं भारतीय गेंदबाज ने भी क्लब के लिए आने वाले दिनों में खेलने के लिए उत्सुकता जाहिर की।

ICC टेस्ट रैंकिंग

ब्रूक नंबर वन बल्लेबाज बने, भारतीय कप्तान गिल आठवें स्थान पर

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा बुधवार को जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पहला स्थान हासिल किया है। ब्रूक ने साथी खिलाड़ी और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। भारतीय कप्तान गिल को 2 स्थान का फायदा हुआ है। गिल आठवें स्थान पर चले गए हैं। लॉर्ड्स में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की 115 रनों की जीत के दौरान पहली पारी में अर्धशतक लगाने के बाद ब्रूक नंबर एक स्थान पर आ गए। ब्रूक पहली बार दिसंबर 2024 में शीर्ष स्थान पर पहुंचे थे। मैच में पचास से अधिक रन बनाने वाले केवल दो खिलाड़ियों में से एक ब्रुक थे। ब्रूक ने पहली पारी में 56 रन बनाए थे। ट्रेविस हेड दूसरे स्थान पर आ गए हैं। हेड को एक स्थान का फायदा हुआ है। जो रूट के लिए लॉर्ड्स टेस्ट अच्छा नहीं रहा था। दोनों पारियों में वह एक और आठ रन ही बना पाए थे। इसका उन्हें नुकसान हुआ है। रूट दो स्थान खिसकर पहले से सीधे तीसरे स्थान पर आ गए हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट में शतक लगाया था। इस शतक की बदौलत दो स्थान ऊपर चढ़कर वह आठवें स्थान पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ चौथे स्थान पर है। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस एक स्थान उपर चढ़कर पांचवें स्थान पर चले गए हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन छठे स्थान पर हैं। उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बवुमा सातवें स्थान पर हैं। भारत के यशस्वी जायसवाल नौवें स्थान हैं। उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है। श्रीलंका के दिनेश चांदीमल एक पायदान उपर चढ़कर दसवें स्थान पर चले गए हैं।

व्यापार

प्लास्टिक के नोट भारत में भी चलेंगे, सोशल मीडिया से शुरू हुई इस कहानी को मिल गया विराम

नई दिल्ली, एजेंसी। इन दिनों सोशल मीडिया पर इस बात का जबरदस्त हल्ला है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जल्दी ही भारत में भी प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। इसके बाद धीरे-धीरे पुराने नोट आउट हो जाएंगे। इसका असर दिखना शुरू हुआ और लोगों ने पुराने या बदहाल नोटों को लेना बंद कर दिया। इसके बाद रिजर्व बैंक को सामने आ कर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी।

सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से करेंसी नोटों के बारे में अजीब दावा किया जा रहा है। एक वीडियो में बताया जा रहा है कि भारत में 30 जून 2026 तक कागज के नोट बंद कर प्लास्टिक करेंसी चलाने की योजना है। इस वीडियो में 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये के नोट बदलने की बात की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित आवाज का भी इस्तेमाल किया गया है।

इस अफवाह से रिजर्व बैंक असहज हुआ। फिर केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाले प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो को सामने

आना पड़ा। उसने रिजर्व बैंक के हवाले से किया। पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे को गलत बताया है। इसके मुताबिक त्रब्द्ध ने स्पष्ट किया है कि कागज के नोटों को वापस लेने या उनकी जगह प्लास्टिक करेंसी जारी करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

सोशल मीडिया के जमाने में पीआईबी ने लोगों से एक अपील भी की। पीआईबी ने कहा कि नोट के बारे में सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ही करें भरोसा करें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी दावे पर नहीं। साथ ही इस तरक के दावे को बिना जांचे-परखे शेयर न करें।

प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो ने लोगों से जागरूक नागरिक बनने को कहा है। उनसे कहा गया है कि यदि सोशल मीडिया पर भारत सरकार से जुड़ा कोई भी संदिग्ध या भ्रामक कंटेंट दिखता है तो उसकी शिकायत करें। यह शिकायत को कर सकते हैं। इस वायरल दावे की सच्चाई अलग है

रिजर्व बैंक ने इस दावे को खारिज किया है वायरल वीडियो फर्जी और डिजिटल रूप से एडिट किया गया है कागजी नोटों को प्लास्टिक करेंसी से बदलने की कोई योजना नहीं है ऐसा नहीं है कि भारत प्लास्टिक के नोट चलाने वाला पहला देश है।

दुनिया के कुछ देशों में प्लास्टिक (पॉलीमर) आधारित नोट चलते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम आदि देश शामिल हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि प्लास्टिक के नोट दरअसल शुद्ध रूप से पन्नी या प्लास्टिक के नोट नहीं होते हैं। ये पॉलीमर से बने होते हैं जिनमें मुख्य रूप से पॉलीप्रोपलीन का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। ये कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होते हैं।

महिंद्रा हर महीने 57,000 पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बना सकती है

महिंद्रा के पॉपुलर एसयूवी का घट गया है प्रोडक्शन, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से है कनेक्शन

नई दिल्ली, एजेंसी। थार, स्कोर्पियो और बोलेरो जैसी लोकप्रिय गाड़ियां बनाने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा की एसयूवी का प्रोडक्शन जून में 15 प्रतिशत तक गिर सकता है। इसकी वजह यह है कि कंपनी को पार्ट्स सप्लाई करने वाले कुछ प्रमुख सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भारी कमी से जूझ रहे हैं। महिंद्रा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत एक बड़े वेंडर की तरफ से सप्लाई में 20-25 प्रतिशत की कमी आई है। इससे कंपनी के फैक्ट्री ऑपरेशन्स पर असर पड़ रहा है। यह कंपनी हर महीने 57,000 पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बना सकती है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग हब में इस समय लेबर की भारी कमी है। इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मिनिमम वेज बढ़ने से प्रवासी मजदूरों के लिए स्थानीय नौकरियां ज्यादा आकर्षक हो गई हैं। इतना ही नहीं वेलफेयर स्कीम्स और ई-रिक्शा जैसे बढ़ते स्वरोजगार के मौकों ने पारंपरिक इंडस्ट्रियल हब की ओर होने वाले पलायन को और कम कर दिया है। इस बारे में महिंद्रा ने श्वञ्ज के सवालों का

कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्ट्रिक ट्रक और बस बनाने वाली पुणे की कंपनी श्व्र मोबिलिटी के फाउंडर और चेयरमैन सुधीर मेहता ने कहा कि पुणे और औरंगाबाद के आस-पास ऑटोमोटिव क्लस्टर में लेबर की उपलब्धता में डिमांड और सप्लाई का साफ अंतर दिख रहा है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर फसल कटाई के सीजन में अपने गांव लौट गए हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में हुई विधानसभा चुनावों के लिए गए प्रवासी वर्कर्स में से भी ज्यादातर लौटकर नहीं आए हैं। यूपी और बिहार में बेहतर आर्थिक अवसरों के कारण भी पश्चिमी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स की ओर पलायन कम हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की एसयूवी का प्रोडक्शन जून में 15 प्रतिशत तक गिर सकता है कंपनी के कुछ प्रमुख सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भारी कमी से जूझ रहे हैं एक बड़े वेंडर की तरफ से सप्लाई में 20-25 प्रतिशत तक की भारी कमी आई है लेबर की कमी सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा से पहले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, स्टील और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म, ईरान युद्ध के बीच सरकार का फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने ज्यादा एथेनॉल मिले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी। अब 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जानकारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से भविष्य में तेल की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही इससे एथेनॉल की मांग बढ़ेगी जिससे किसानों को भी फायदा होगा।

ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई है। यह 114 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। इससे सरकार का आयात बिल बढ़ गया है और चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है। इसका असर रुपये पर भी दिख रहा है और डॉलर के मुकाबले इसमें काफी गिरावट आई है। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा बड़ा आयातक और उपभोक्ता है। यही वजह है कि सरकार वैकल्पिक ईंधन पर जोर दे रहा है ताकि आयात में कमी की जा सके।

सरकार ने हायर एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है लेकिन टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह

संभव है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का लेवल बढ़ाने का आदेश न दे, बल्कि फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के बारे में फैसला खरीदारों पर छोड़ दे। इसकी वजह यह है कि कई लोगों ने चिंता जताई है कि श्व20 से श्व25 पर तेजी से जाने से मौजूदा गाड़ियों के इंजन खराब हो सकते हैं।

2012 और मार्च 2023 के बीच बनी ज्यादातर कारें और दो-पहिया गाड़ियां श्व10 के अनुकूल थीं। इसी तरह अप्रैल 2023 से बनी गाड़ियां के अनुकूल थीं यानी उन्हें 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिले पेट्रोल के साथ चलने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अप्रैल 2025 से बेची जाने वाली गाड़ियां ही पूरी तरह से अनुकूल हैं। स्टैंडर्ड तैयार कर रही है, जिससे पेट्रोल में 30 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाने की इजाजत मिल सकेगी। इसके अलावा श्व25 गाड़ियों के लिए ट्रायल भी शुरू किए जा रहे हैं।

हालांकि, इंडस्ट्री फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां लाने के लिए तैयार है। मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां सड़कों पर आ चुकी हैं और दूसरी कंपनियां भी अपनी लॉन्च की योजनाएं तैयार कर रही हैं। ऑटो इंडस्ट्री ने ब्लेंडिंग में बढ़ोतरी को धीरे-धीरे लागू करने का सुझाव दिया है। वे राज्य इसकी वकालत कर रहे हैं जहां गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। इसके अलावा, ताकतवर शुगर लॉबी भी इसकी वकालत कर रही है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स

ऑटो इंडस्ट्री के अधिकारियों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर पेट्रोल गाड़ियां फ्यूल के साथ भी पूरी तरह से मटीरियल और फ्यूल के हिसाब से कम्प्लायंट नहीं हैं। इसलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग में कोई भी अनिवार्य बढ़ोतरी न सिर्फ माइलेज कम करेगी बल्कि ऐसी गाड़ियों के मेंटेनेंस का खर्च भी बढ़ाएगी। इससे वीकल ओनर्स का एक बड़ा हिस्सा

एलजी का भारत समेत तीन प्रमुख ग्लोबल साउथ बाजारों से 2030 तक राजस्व दोगुना करने का लक्ष्य

नई दिल्ली, एजेंसी। दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलजी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ल्यू जे-चोल ने कहा कि कंपनी भारत सहित तीन उच्च संभावनाओं वाले ग्लोबल साउथ बाजारों से अपना कुल राजस्व साल 2030 तक दोगुना करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि भारत में मजबूत वृहद आर्थिक वृद्धि, ब्रांड के प्रति उपभोक्ताओं की पसंद तथा रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसी प्रमुख श्रेणियों में घरेलू उपकरणों की अपेक्षाकृत कम पहुंच के कारण बड़े अवसर मौजूद हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ ने कहा कि भारत, सऊदी अरब और ब्राजील कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि की रणनीति के केंद्र में हैं। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक इन तीनों बाजारों से संयुक्त राजस्व को दोगुना करना है और इसके लिए वह इन उच्च संभावनाओं वाले बाजारों में अपने कारोबार का तेजी से विस्तार कर रही है। जे-चोल ने कहा, 2025 में इन क्षेत्रों से हमारा संयुक्त राजस्व 6.2 लाख करोड़ कोरियाई वॉन रहा, जो 2023 की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। यह कंपनी की वैश्विक वृद्धि से दोगुना से भी अधिक है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का 2025 में एकीकृत राजस्व 89.2 लाख करोड़ कोरियाई वॉन रहा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे प्रमुख उभरते बाजारों में तेज वृद्धि केवल कारोबार का विस्तार नहीं, बल्कि दक्षिण कोरिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में

कंपनी की मजबूत उपस्थिति के पूरक के रूप में संतुलित और मजबूत क्षेत्रीय पोर्टफोलियो तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी की ग्लोबल साउथ रणनीति के तहत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिये उत्पाद नेतृत्व को मजबूत करने तथा सह-विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन के माध्यम से लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कंपनी की मध्यम से दीर्घावधि की रणनीति के बारे में विस्तार से बताते हुए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की निवेशक संबंध (आईआर) संचार टीम के प्रमुख एयरोन किम ने कहा कि कंपनी अपने मुख्य कारोबार को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, जिसमें घरेलू उपकरण, वाहन तथा मीडिया एवं मनोरंजन समाधान शामिल हैं। भारत में योजनाओं के बारे में किम ने कहा कि कंपनी यहां अपनी उत्पादन क्षमता दोगुनी करेगी और अतिरिक्त क्षमता का उपयोग निर्यात बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)